हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 179 बेमेतरा, गुरुवार 19 फरवरी 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

साइबर अपराधियों के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने साइबर धोखाधड़ी में अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब उन्होंने म्यूल बैंक खातों का निर्माण कर उन्हें साइबर अपराधियों को बेचने के एक आरोपित परमजीत खरब को जमानत दे दी। म्यूल बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल साइबर ठग हड़पी गई रकम को ट्रांसफर कराने के लिए करते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसडी संजय से कहा कि सरकार और पुलिस को कमजोर पीड़ितों विशेषकर बुजुर्गों की सुरक्षा और मुआवजे के लिए कदम उठाने चाहिए।

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत, तेज रफ्तार बनी काल

नागदा। मध्य प्रदेश के नागदा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई। हादसा नागदा-महिदपुर रोड पर रूपेटा गांव के समीप हुआ, जहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक बाइक पर इंदौर जिले के देपालपुर निवासी आबेद और अनवर सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर डाक विभाग के कर्मचारी राहुल गुर्जर सवार थे। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं और अचानक आमने-सामने आ गईं, जिससे भयंकर टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने 112 इमरजेंसी नंबर पर सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। यह दुर्घटना नागदा मंडी थाना क्षेत्र में हुई। प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीडिंग और संभवत: लेन क्रॉसिंग को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।

सोने की खदान के नाम पर 1.90 करोड़ की ठगी, आरोपी मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

रायपुर। तंजानिया में सोने की खदान में निवेश के नाम पर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश भागने की फिराक में था, जिसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी यश राजेश शाह (28 वर्ष), निवासी घाटकोपर पूर्व मुंबई, ने प्रार्थी समर्थ बरडिया और उसके साथी को तंजानिया में सोने की खदान होने का झांसा दिया था। आरोपी ने खुद को खदान का मालिक बताते हुए पार्टनरशिप में निवेश कराने के नाम पर फर्जी अनुबंध तैयार किया और उनसे बड़ी रकम वसूल ली।

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का हुआ ऐलान

26 फरवरी को नोटिफिकेशन 16 मार्च को होगा वोटिंग

नई दिल्ली/ एजेंसी

चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 खाली राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है. 16 मार्च को मतदान होगा. चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे. मतदान सुबह नौ से शाम चार बजे तक चलेगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. यह चुनाव अप्रैल की शुरुआत में खाली हो रही सीटों के लिए आयोजित किया जा रहा है. राज्यसभा की इन 37 सीटों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सात सीटें खाली हो रही हैं. इसके अलावा तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल से पांच-पांच सीटें रिक्त होंगी. ओडिशा से चार और असम से तीन सीटों पर चुनाव होंगे. हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से दो-दो सीटों, जबकि हिमाचल प्रदेश से एक सीट पर मतदान होगा. इन सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच पूरा हो रहा है. उनके रिटायरमेंट के बाद नए सांसद शपथ लेंगे. बिहार की 5 राज्यसभा सीटें भी अप्रैल में खाली हो रही हैं. रिटायर होने वाले प्रमुख चेहरों में राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह शामिल हैं. इसके साथ ही, मोदी कैबिनेट के मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा

है. आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी से अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद गुप्ता भी इसी लिस्ट में हैं. बिहार की इन महत्वपूर्ण सीटों पर नए चेहरों के आने या पुराने सांसदों की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. महाराष्ट्र से शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास आठवले जैसे बड़े नेता रिटायर हो रहे हैं. तमिलनाडु से एम तंबीदुरै, तिरुचि शिवा और कनिमोझी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. पश्चिम बंगाल से साकेत गोखले और ऋ्नब्रत बनर्जी जबकि असम से रामेश्वर तेली विदा होंगे. छत्तीसगढ़ से केटीएस तुलसी, हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का नाम भी शामिल है. तेलंगाना से कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी रिटायर हो रहे हैं. इन सभी के स्थान पर अब नए सांसदों का चुनाव होगा. राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 को चुनाव होंगे। उसी दिन शाम के पांच बजे से वोटों की गिनती शुरु हो जाएगी। राज्यसभा के चुनाव लोकसभा से बहुत अलग होते हैं। यहां जनता सीधे वोट नहीं डालती। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभाओं के विधायक चुनते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 को राष्ट्रपति नामित करते हैं।

बिहार, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों का समीकरण

बिहार (5 सीटें): यहाँ जदयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर, जबकि राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हालिया विधानसभा चुनावों के बाद बदले समीकरणों के कारण भाजपा और जदयू गठबंधन यहाँ मजबूत स्थिति में है।

छत्तीसगढ़ (2 सीटें): कांग्रेस की फूलो देवी नेताम और के. टी. एस. तुलसी निवृत्त हो रहे हैं। राज्य में भाजपा की सरकार होने के कारण ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाने की प्रबल संभावना है।

हरियाणा (2 सीटें) व हिमाचल (1 सीट): हरियाणा में भाजपा की किरण चौधरी और हिमाचल में इंदु गोस्वामी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद पिछले राज्यसभा चुनाव के अनुभवों को देखते हुए यहाँ मुकाबला रोचक हो सकता है।

कट्टर कांग्रेसी क्यों हो रहा भाजपाई

गठबंधन की बातचीत को लेकर उन्हे जलील किया

असम। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा का भाजपाई होना तय हो चुका है। बीते कल तक वे किसी का नाम लेकर आरोप लगाने से बच रहे थे, लेकिन आज यानी बुधवार को उन्होंने खुलकर पूरी कहानी बयां कर दी है। इस दौरान उन्होंने असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले भूपेन कुमार बोरा को मनाने में कांग्रेस नाकाम रही है। अब कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को वह भाजपा ज्वाइन करेंगे। पहले उन्होंने इस्तीफा वापसी के संकेत दिए थे, मंगलवार की शाम को हिमंत बिस्व सरमा से

मुलाकात के बाद उन्होंने इरादा बदल दिया है। इस बीच बुधवार को भाजपा ज्वाइन करने की ख़बरों की पुष्टि करते हुए भूपेन बोरा ने कहा कि वह हिमंत के घर जाकर इस विषय में बात करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने पहली बार कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला है।

कब्र पर कलह

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को कब्र में दफनाने पर लगाई रोक,सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया..... ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों के अंतिम संस्कार को लेकर उपजा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आदिवासी ईसाइयों को उनके अपने ही गांवों में दफनाने से रोका जा रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि फिलहाल किसी भी शव को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह याचिका 'छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वैलिटी' की ओर से दायर की गई है। याचिका में 143 ऐसे परिवारों का विवरण दिया गया है, जिन्हें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि कुछ मामलों में पुलिस की मौजूदगी में शवों को कब्र से खोदकर निकाला गया और फिर गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर दोबारा दफनाने के

लिए भेजा गया। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि अदालत गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार को एक मौलिक अधिकार घोषित करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि धर्म या जाति के आधार पर श्मशान या कब्रिस्तान में भेदभाव न किया जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर और आसपास के आदिवासी अंचलों में यह समस्या गहरी होती जा रही है। दरअसल, यहां के गांवों में अंतिम संस्कार की जगहें और रीतियां सदियों पुरानी सामुदायिक परंपराओं पर आधारित हैं। जब कोई परिवार ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसकी अंतिम विदाई की पद्धति बदल जाती है। ग्राम सभा और पारंपरिक समुदाय का तर्क होता है कि धर्म बदलने के बाद व्यक्ति की जड़ें उस पारंपरिक कब्रिस्तान से कट जाती हैं, जबकि ईसाई परिवारों का कहना है कि धर्म बदलने से उनकी नागरिकता या गांव का हक खत्म नहीं हो जाता।

कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम का फैसाला- पायजामे का नाड़ा खींचना दुष्कर्म की कोशिश

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पायजामे का नाड़ा खींचना और स्तन छूना साफ तौर पर दुष्कर्म की कोशिश है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवादित फैसला भी पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि नाड़ा खींचना या तोड़ना सिर्फ दुष्कर्म करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की और 10 फरवरी को उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने का आदेश दिया। इसके

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ लगे सख्त आरोपों को भी बहाल कर दिया। 10 नवंबर 2021 को एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि वह और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी उसकी ननद के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनके गांव के ही पवन, आकाश और अशोक ने उनकी बेटी को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने की पेशकश की। महिला ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की और उसके पायजामे का नाड़ा भी खींच लिया। बच्ची की चीख सुनकर दो लोग वहां पहुंचे और उन्हें देखकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि विवादित आदेश आपराधिक न्यायशास्त्र के तय सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल के कारण रद्द किया जाता है।

धुरंधर 2 शूटिंग में नियम तोड़ने पर बीएससी सख्त

मुंबई । आदित्य धर की मोस्टअवेटेड स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज (धुरंधर 2) की शूटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों के बार-बार उल्लंघन के आरोप में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आदित्य धर की प्रोडक्शन कंपनी बी62 स्टूडियोज को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए बीएमसी के ए-वार्ड कार्यालय ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) को पत्र लिखकर स्टूडियो पर राज्य के सिंगल-विंडो फिल्मिंग पोर्टल के माध्यम से शूटिंग पर स्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है।

एक्टिव हुई यूपी पुलिस,प्रशासन-छात्रों के बीच झड़प

मोहन भागवत गो बैक के नारों से गूंज उठी लखनऊ यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बुधवार सुबह उस समय सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंचे। उनके दौरे के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंपस में जमकर नारेबाजी की जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक और खींचतान देखने को मिली। लखनऊ विश्वविद्यालय में संघ के शताब्दी समारोह के सिलसिले में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए जैसे

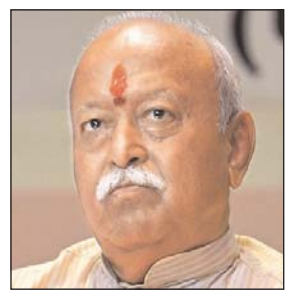

ही मोहन भागवत का आगमन हुआ, वहां पहले से तैयार छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शन में एनएसयूआई समाज वादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में शामिल थे। इकट्ठे हुए छात्रों ने गो बैक मोहन भागवत के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे कुछ ही देर में कैंपस का माहौल गरम हो गया। छात्रों का तर्क था कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विरोध इतना मुखर था कि पुलिस प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन उठाकर जीप और बसों में भरना शुरू किया।

पीएम से मुलाकात के बाद बोले गूगल प्रमुख पिचाई

भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार...

नई दिल्ली/ एजेंसी

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पिचाई भारत में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आए हैं और 20 फरवरी को समिट में मुख्य भाषण देंगे। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत पहुंचने पर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत लौटकर खुशी हो रही है और यहां हमेशा की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान श्री सुंदर पिचाई से मिलकर बेहद खुशी हुई। हमने एआई के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कार्यों और इस क्षेत्र में हमारे प्रतिभाशाली छात्रों और पेशेवरों के साथ गूगल कैसे काम कर सकता है, इस बारे में चर्चा की। पिचाई ने कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है और गूगल देश के एआई परिवर्तन में साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एआई हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बदलाव है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर डायग्नोस्टिक्स से लेकर किसानों को रियल-टाइम अलर्ट देने जैसे बड़े स्तर की चुनौतियों को हल करने में सक्षम है। पिचाई ने भारत की

विविधता, बहुभाषी पारिस्थितिकी और मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नवाचार के लिए मजबूत आधार बताते हुए कहा कि यह वैश्विक स्तर पर एआई के लोकतांत्रिक उपयोग का एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने जोर दिया कि एआई का विकास भरोसे, सुरक्षा और समावेशिता को प्राथमिकता देते हुए होना चाहिए, ताकि तकनीक स्थानीय भाषाओं और संदर्भों में लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचा सके। इस दौरान पिचाई ने 'इंडिया-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव' की भी घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका, भारत और दक्षिणी गोलार्ध के कई क्षेत्रों के बीच एआई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए सबसी केबल रूट विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गूगल भारत में फुल-स्टैक कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है और भविष्य को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने भारत में 15 अरब डॉलर के एआई हब की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें गीगावॉट-स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे शामिल होगा, जिससे रोजगार सृजन और उन्नत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही गूगल ने स्किलिंग कार्यक्रमों की भी घोषणा की, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल है, जो छात्रों और शुरुआती करियर के पेशेवरों को लक्षित करेगा।

अब 6जी और एआई में साथ काम करेंगे भारत-फिनलैंड, दिल्ली में पीएम मोदी और पेटेरी ओर्पो की अहम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के इतर फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने इस चर्चा को दोनों देशों के भविष्य के लिए बेहद अहम करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारत और फिनलैंड का प्राथमिक उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना करना है।

तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतियोगिता शुरू, पहले मैच में उत्तर प्रदेश ने गंगालूर को हराया

बीजापुर में वॉलीबॉल का बड़ा आयोजन, देशभर की टीमें ले रहीं हिस्सा

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले के मिनी स्टेडियम में बिते बुधवार से अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस तीन दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के चलते शहर में खेल प्रेमियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट में इनकम टैक्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जबलपुर रेलवे, छत्तीसगढ़ पुलिस, साई तमिलनाडु, उड़ीसा और तेलंगाना की टीमें मैदान में उतरी हैं। पहले दिन से ही मुकाबले तेज और प्रतिस्पर्धी नजर आए। खिलाड़ियों के दमदार सर्व, मजबूत ब्लॉक और आक्रामक स्मैश ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं वॉलीबॉल संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश गागड़ा, जिला पंचायत की सीईओ नम्रता चौबे, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी और मथियास कुजूर, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, जिला खेल अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल तथा एसडीएम जागेश्वर कौशल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।उद्घाटन मुकाबला गंगालूर और उत्तर प्रदेश की टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन अंत में उत्तर प्रदेश ने जीत दर्ज की। खिलाड़ियों की ऊर्जा और तालमेल ने संकेत दे दिया है कि आने वाले मुकाबले और भी दिलचस्प होंगे।आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है, बल्कि जिले में खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। अगले दो दिनों तक मिनी स्टेडियम खेल उत्साह और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहेगा।

कोटपा एक्ट-2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संयुक्त शासकीय दल की कार्रवाई, 23 प्रकरणों में अर्थदंड

कांकेर /मूक पत्रिका

बीते बुधवार को जिले में तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के स्पष्ट एवं कड़े निर्देशों के बाद कोटपा एक्ट-2003 के तहत व्यापक एवं ताबड़तोड़ जांच अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने भानुप्रतापपुर, संबलपुर एवं ग्राम केंवटी में एक साथ दबिश देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी कार्रवाई की। अभियान के दौरान स्कूलों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 23 चालान काटे गए तथा 3100 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ÷नशा मुक्त भारत अभियान÷ के तहत विद्यार्थियों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई तथा कोटपा एक्ट की धाराओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला पंचायत सभाकक्ष में श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन आयोजित, 8,704 हितग्राहियों को 2.60 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में बीते बुधवार को श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 400 श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर शासन की विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं सुझावों को मंच के माध्यम से रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक दिपेश साहू, नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, पार्षद सुश्री नीतू कोठारी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रेमलता पदमाकर तथा श्रम पदाधिकारी शोएब काजी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि योगेश दत्त मिश्रा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा विभिन्न योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को मजबूती प्रदान करना है। इस अवसर पर विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 8,704 हितग्राहियों को 2,60,82,000/- (दो करोड़ साठ लाख बयासी हजार) रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। योजनानुसार लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण इस प्रकार है– मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 239 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 18 हितग्राही, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 10 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 128 हितग्राही, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 22 हितग्राही, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 8,287 हितग्राही, कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए तथा अन्य हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पदमाकर ने बताया कि श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से अपील की कि वे अपने दस्तावेज अद्यतन रखें एवं योजनाओं की जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क बनाए रखें।

सम्मेलन का उद्देश्य श्रमिकों को जागरूक करना, योजनाओं की जानकारी देना तथा शासन और श्रमिकों के बीच संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों ने शासन की पहल की सराहना करते हुए इसे लाभकारी बताया। इस प्रकार श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन ने श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त एवं जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो प्रकरण में विभागीय जांच प्रारंभ, संबंधित अधिकारी लाइन अटैच

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कांकेर :- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक वीडियो के संबंध में, जिसमें दमकसा चौकी में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी को ग्रामीणों से राशि लेते हुए प्रदर्शित किया गया है, उक्त प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार संबंधित अधिकारी, एएसआई रजनीश गजभिए बीते मंगलवार को एमवी एक्ट अंतर्गत वाहन चेकिंग ड्यूटी पर तैनात थे।

मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन पर ?500 का चालान विधिवत किया गया एवं उसकी अधिकृत रसीद प्रदान की गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाहन चालक एवं उसके सहयोगी द्वारा राशि एकत्र कर चालान जमा किया गया। तथापि, वीडियो में प्रदर्शित संवाद एवं व्यवहार की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला कांकेर द्वारा संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन अटैच किया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं किया जाएगा।

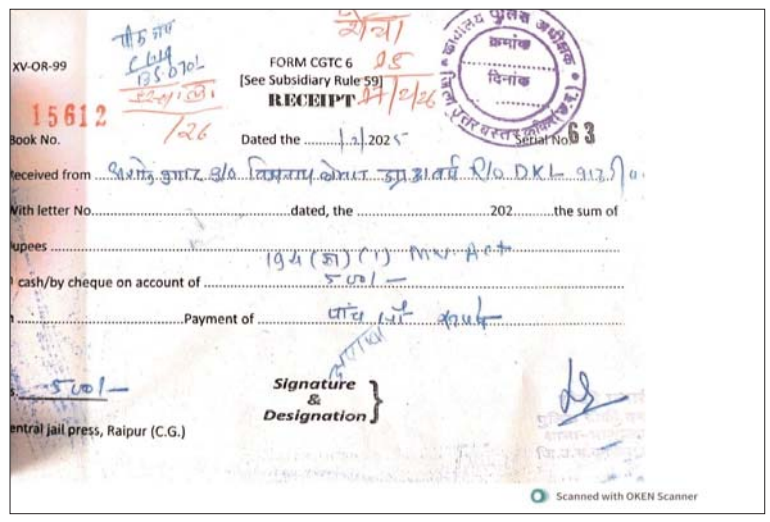

स्मार्ट मीटर से डरे नहीं यह सिर्फ अफवाह है ईई विद्युत पी सी महानंदा

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही उलझन व अफवाहों के बीच विद्युत विभाग के अधिकारी प्रफुल्ल चंद्र महानंदा ने कहा कि, स्मार्ट मीटर पूरी तरह भरोसेमंद है और इनमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। स्मार्ट मीटर पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करते हैं। इनमें इंसानी हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए गलत रीडिंग या गलत बिल की संभावना बहुत कम रहती है। साथ ही इससे बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी। मीटर लगाने के बाद उसकी जानकारी एसएपी सिस्टम में दर्ज की जाती है। इसके बाद नया बिल स्मार्ट मीटर की रीडिंग के आधार पर जारी होता है। उपभोक्ताओं के सवालों पर प्रफुल्ल चंद्र महानंदा ने बताया कि, कुछ मामलों में मानवीय भूल से मीटर की जानकारी दर्ज नहीं हो पाती, जिससे औसत बिल जारी हो जाता है। ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर विभाग तुरंत सुधार करता है और पहले जारी औसत बिल को समायोजित कर देता है। अगर किसी उपभोक्ता को एकमुश्त ज्यादा बिल मिलता है तो नियम के अनुसार स्लैब की सुविधा देकर बिल को समायोजित किया जाता है। स्मार्ट मीटर या बिलिंग से जुडी किसी भी समस्या के लिए संबंधित फील्ड ऑफिसर से संपर्क करें ।

समग्र शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल से बहुदिव्यांग छात्रा गुंजन को मिली नई राह

कांकेर /मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक शाला सलिहापारा तुएगुहन की कक्षा दूसरी की बहुदिव्यांग छात्रा कु. गुंजन सुरेंद्र को आज समग्र शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में व्हीलचेयर एवं एमआर किट प्रदान की गई।समग्र शिक्षा विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। दोनों विभागों के समन्वित प्रयास से गुंजन को यह आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे अब वह नियमित रूप से विद्यालय आ-जा सकेगी। व्हीलचेयर मिलने से छात्रा के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पूर्व में परिजनों को उसे गोद में उठाकर विद्यालय लाना पड़ता था, जिससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस सुविधा से न केवल पढ़ाई सुचारु होगी, बल्कि छात्रा का आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। समग्र शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की यह संवेदनशील पहल समावेशी शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। इस कार्य से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है तथा परिवार में खुशी का माहौल है।

बेमेतरा में श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन आयोजित, श्रमिकों को मिला शासन की योजनाओं का लाभ

रायपुर /मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में बीते बुधवार को जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में श्रमिक जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा दिपेश साहू, नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष विजय सिन्हा, पार्षद सुश्री नीतू कोठारी, राजेन्द्र शर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्रीमति प्रेमलता पदमाकर, श्रम पदाधिकारी शोएब काजी उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में लगभग 400 श्रमिक उपस्थित हुए। अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा के द्वारा श्रमिको को योजनाओ के लाभ एवं उनकी समस्याओं के संबंध में संवाद किया गया।कार्यक्रम के माध्यम से मिनीमाता महतारी जतन योजना के 239 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के 18 हितग्राही, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 10 हितग्राही, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के 128 हितग्राही, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के 22 हितग्राही, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृति योजना के 8287 हितग्राही, कुल 8704 हितग्राहियों को राशि 2 करोड़ 60 लाख 82 हजार रूपए से लाभांवित किया गया।

सड़क निर्माण का काम अधूरा छोड़ गायब हुआ ठेकेदार, ग्रामीण परेशान

परसदा,डोटमा सड़क निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार घिरे आरोपों से

सक्ती/हसौद/मूक पत्रिका

दरअसल पूरा मामला परसदा ग्राम पंचायत से लेकर डोटमा तक नवीन प्रधानमंत्री सड़क निर्माण को लेकर सामने निकल कर आ रहा है। जहाँ बीते 2023 में परसदा गांव से लेकर डोटमा तक 3.25 किलीमीटर तक सड़क निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था। परंतु गांव के स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के शुरुआती दौरान पर ही निर्माण का काम ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मामला तीस साल पुराना बताया जा रहा है। हसौद ब्लॉक में परसाद गांव से लेकर डोटमा गांव तक 3.25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना था।

बता दे एक तरफसरकार लोगों को आवागमन करने में कोई असुविधा न हो इसलिए करोड़ों रुपये खर्च सड़क का निर्माण करवा रही है तो वहीं प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार

शासकीय राशि को गबन का तरीका ढूढंकर राशि को गबन कर लेते हैं ऐसा ही एक मामला जिले जैजैपुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम परसदा से डोटमा पहुंच मार्ग में सामने आया है जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत परसदा से डोटमा तक जाने के लिए पक्की सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी दूरी लगभग 3.25किमी है। इसके लिए हिल ब्रो मेटालिक्स एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी रायगढ़ को यह ठेका दिया गया था। लेकिन इस रोड पर करीब दो साल से निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। ठेकेदार ने सड़क पर कुछ भी कार्य नही किया है। गर्मी में सड़क पर पानी नहीं डाले जाने से धूल और डस्ट से राहगीरों का इस रोड पर चल पाना मुश्किल हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है।लेकिन जिम्मेदारों को लोगों की परेशानी से कोई मतलब नही है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार केवल सूचना बोर्ड लगाकर बीते वर्षो से गायब है। इसके बाद भी अधूरे निर्माण कार्य को लेकर जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारी के कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा मार्ग में डामरीकरण व चौड़ीकरण करने के लिए लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। अब जब सड़क निर्माण की मंजूरी ठेकेदार हिल ब्रो मेटालिक्स कम्पनी को मिली है तो उसने केवल सूचना बोर्ड लगाकर निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार एवं इंजीनियर एवं विभागीय अधिकारी इन सभी ने सड़क निर्माण के राशि का गबन कर लिया है इसलिए निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।अब देखना होगा कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर अन्य मामलों की तरह इसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।

धान खरीदी 2025-26 में एमसीबी आगे, अब तक 4.01 लाख क्विंटल धान का सुरक्षित परिवहन

धान उठाव में एमसीबी जिला बना मिसाल, 45 प्रतिशत से अधिक धान का सुरक्षित परिवहन पूर्ण

एमसीबी/मूक पत्रिका

धान खरीदी वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में उपार्जित धान का उठाव कार्य तेज, सुव्यवस्थित और पूरी तरह किसान हितैषी तरीके से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप जिले में धान उठाव की प्रक्रिया निरंतर सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है, जिससे उपार्जन केंद्रों से धान का सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित हो रहा है।जिले में अब तक कुल 8,79,848.60 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया है, जिसमें से 4,00,910.00 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उठाव हो चुका है। यह कुल उपार्जित धान का लगभग 45.57 प्रतिशत है। शेष 4,78,938.60 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में सुरक्षित रूप से संग्रहित है, जिसे उठाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चरणबद्ध और

प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

उपार्जन केंद्रवार उठाव की स्थिति पर नजर डालें तो कछौड़ से 10,940 क्विंटल, केल्हारी से 37,410 क्विंटल, कटकोना से 1,790 क्विंटल, कोड़ा से 16,970 क्विंटल, कौड़ीमार से 35,260 क्विंटल, खड़गवां से 20,930 क्विंटल, बरदर से 29,890 क्विंटल, रतनपुर से 19,650 क्विंटल, सिंगहत से 15,190 क्विंटल, कुंवारपुर से 14,420 क्विंटल, घुटरा से 23,330 क्विंटल, कठौतिया से 22,400 क्विंटल, चैनपुर से 30,860 क्विंटल, नागपुर से 24,040 क्विंटल, बंजी से 17,740 क्विंटल, जनकपुर से 11,410 क्विंटल, बहरासी से 6,240 क्विंटल, डोडकी से 18,960 क्विंटल, माड़ीसरई से 11,620 क्विंटल, सिंगरौली से 900 क्विंटल तथा बरबसपुर से 30,960 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। कई केंद्रों पर उठाव शून्य रहने के बावजूद वहां भी आगामी दिनों में कार्य तेज करने की तैयारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में धान उठाव को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास और उनकी मेहनत के सम्मान से जुड़ा दायित्व माना जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रत्येक उपार्जन केंद्र की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि शेष धान का उठाव समय पर, सुरक्षित और बिना किसी असुविधा के पूरा किया जा सके।कुल मिलाकर धान खरीदी वर्ष 2025-26 में जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का धान उठाव कार्य एक सशक्त और अनुकरणीय उदाहरण के रूप में सामने आया है। सुनियोजित कार्यप्रणाली, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच के चलते यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपार्जित धान का उठाव पूरी पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो।

वाद-विवाद कर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

प्रार्थी पंचुराम साहू उम्र 55 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 02 परपोडी थाना परपोडी, जिला बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 फरवरी 2026 के रात्रि करीबन 01:30 बजे करण साहू निवासी मासुलगोंदी के द्वारा बजरंग बली मंदिर के पास ग्राम तुमडीपार में इसके लडके बलराम साहू से वाद-विवाद कर उसकी हत्या करने की नियत से उसके पेट में धारदार वस्तु से मार कर प्राणघातक हमला कर चोट पहुचाया है कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 109 क्व्हस् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय को थाना स्टाफ के साथ प्रकरण की विवेचना कार्यवाही में लगाया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी करण साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी मासुलगोंदी को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी करण साहू से पूछताछ में पता चला कि बलराम साहू से आपस में वाद-विवाद होने पर हत्या करने की नियत से धारदार वस्तु से हमला कर गंभीर चोंट पहुंचना।आरोपी करण साहू पिता दुर्गा साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी मासुलगोंदी, थाना परपोडी जिला बेमेतरा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी परपोडी निरीक्षक सत्य प्रकाश उपाध्याय, प्रधान आरक्षक येमन बघेल, डामेश्वर सिंह राजपूत, आरक्षक पीयुष सिंह, शिव कुमार, रमेश चंद्रवंशी, प्रदीप कौशल, प्रमोद पांडेय सहित थाना परपोडी के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

धुम्मा गोडरी नदी में रेत का अवैध खनन, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

अनूपपुर/मूक पत्रिका

जिले के भालूमाड़ा थाना तथा फुनगा चौकी क्षेत्र अंतर्गत धुम्मा गोडरी नदी में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक-एक दिन छोड़कर लगातार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत माफिया सक्रिय रहते हैं और ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी का दोहन किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात भर ट्रैक्टर नदी से रेत निकालकर विभिन्न स्थानों तक पहुंचाते हैं। आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं खनिज विभाग की शिथिल कार्यप्रणाली के कारण रेत चोरों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नदी का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रेत माफिया प्रशासन से एक कदम आगे रहते हुए रणनीति के तहत काम करते हैं। नदी से मुख्य सड़क तक आने वाले तिराहों और रास्तों पर उनके लोग निगरानी में तैनात रहते हैं। किसी भी प्रकार की आशंका होते ही वे ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो जाते हैं।स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

7.57 करोड़ रुपए की लागत से दो सड़कों का भूमिपूजन 19 फरवरी को

भूमिपूजन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा होंगे शामिल

कवर्धा/मूक पत्रिका

कबीरधाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास को गति देते हुए 7 करोड़ 57 लाख 68 हजार रुपए की लागत से दो सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। बटुरा कछार से मदनपुर तक प्रधानमंत्री पक्की सड़क निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 69 लाख 81 हजार रुपए तथा खडौदा से मदनपुर तक प्रधानमंत्री पक्की सड़क निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 87 लाख 87 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दोनों सड़कों का भूमि पूजन 19 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में उप

मुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से स्वीकृत इस राशि से क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सुगम मार्ग मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, उपाध्यक्ष गणेश तिवारी, प्रकाश चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि खेमराज साहू, विजय पटेल जनपद सदस्य श्रीमती छैली सुरेंद्र चंद्रवंशी, रूपेश चंद्रवंशी, रतन चंद्रवंशी, रमेश साहू, सरपंच उमेंद्र टंडन, चौतराम साहू, लखन साहू, श्रवण चंद्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भूमिपूजन में शामिल होगें।

चिरमिरी में सट्टा सिंडिकेट पर कसा पुलिस का शिकंजा, मोबाइल बना राज खोलने की चाबी, मुख्य संचालक गिरफ्तार

एमसीबी/चिरमिरी। मूक पत्रिका

अवैध सट्टा कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए चिरमिरी पुलिस ने संगठित गिरोह के मुख्य संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के निर्देश पर चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर शिव राम पनिका को हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी क्षेत्र में लंबे समय से सट्टे का अवैध नेटवर्क संचालित कर रहा था और मोबाइल के माध्यम से लेन-देन और संपर्क बनाये रखता था।गिरफ्तारी के दौरान जब्त किये गये मोबाइल फोन की जांच में कई संदिग्ध वित्तीय ट्रांजेक्शन, संपर्क सूत्र और सट्टे से जुड़े रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह डिजिटल साक्ष्य पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में अहम साबित हो सकता है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने कहा कि अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इस कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा। पुलिस अब मोबाइल डाटा के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है।

बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक कला के संगम से गुंज उठा 'नियाग्रा' का तट

जगदलपुर/मूक पत्रिका

विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के समीप मेला स्थल में बुधवार को 'चित्रकोट महोत्सव 2026' का शानदार आगाज़ हुआ, जहाँ बस्तर की माटी की सोंधी खुशबू और लोक कलाओं के विविध रंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चित्रकोट महोत्सव 2026 के शुभारंभ के अवसर पर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की दिशा में सरकार प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा सांस्कृतिक, कला और खेल गतिविधि के माध्यम पर्यटन स्थल में चित्रकोट महोत्सव को बढ़ावा दिया जा रहा है । विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप ने भी संबोधित करते हुए चित्रकोट महोत्सव एक सांस्कृतिक महोत्सव के लिए समृद्ध जनजाति संस्कृति का प्रतीक है। शासन द्वारा आयोजित इस समारोह में दो दिवसीय महोत्सव में खेलगतिविधि, कला संस्कृति, पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री बलदेव मंडावी, नगर पालिक निगम सभापति श्री खेमसिंह देवांगन, जनपदों के अध्यक्ष, सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, सहित आईजी श्री सुंदरराज पी, सीसीएफ श्री आलोक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।महोत्सव के प्रथम दिन की शुरुआत स्थानीय स्कूली छात्र-छात्राओं की ऊर्जावान प्रस्तुतियों के साथ हुई। सेजेस अलनार और अंग्रेजी माध्यम स्कूल धाराउर के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वहीं प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास गढ़िया और चित्रकोट सहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं ने लोक संस्कृति पर आधारित नृत्यों से कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। स्कूली कलाकारों की इन प्रस्तुतियों ने मंच पर एक ऐसी जीवंतता पैदा की, जिसने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। अतिथियों ने स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया ।

उड़ीसा के बरगढ़ जिले में राष्ट्रीय दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा आयोजन

जिले के 4 खिलाड़ियों का हुआ चयन

जांजगीर-चांपा /मूक पत्रिका

दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत पहली बार नेशनल दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले के लेंगू मिश्रा क्रिकेट स्टेडियम में (डी.सी.सी.बी.आई) दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफइंडिया द्वारा 21 से 23 फरवरी तक किया जा रहा है। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जिसमें 04 राज्यों छत्तीसगढ़, उडीसा, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात की टीमों द्वार संयुक्त रूप से भागीदारी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य से जांजगीर-चांपा के चार खिलाड़ियों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया है। इनमें धनंजय यादव (कप्तान), केशव चौहान, राकेश कश्यप तथा अमित बरेठ शामिल हैं। जिले से चयनित खिलाड़ियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे द्वारा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की गई है।

बजट : कर्जदार से कंगाली की ओर बढ़ता राज्य : माकपा

भोपाल /मूक पत्रिका

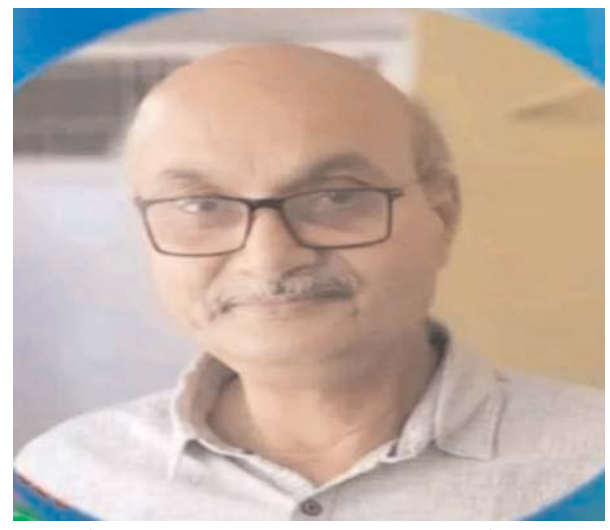

जिस सरकार ने वार्षिक बजट पेश करने से एक दिन पहले ही 19287 करोड़ रूपये का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया होद्य जिस सरकार को बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 5700 करोड़ रूपये का कर्ज लेना पड़ा हो द्य उस सरकार के वार्षिक बजट के क्या मायने हो सकता है । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा है कि प्रदेश की बदतर होती आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 फ़रवरी तक वित्तीय वर्ष के 321 दिनों में मोहन यादव सरकार ने 17 बार कर्ज लिया है द्य औस्तन हर 19 दिन में सरकार कर्ज लेने को बाध्य हो द्य जो सरकार एक माह भी बिना कर्ज लिए चलने की स्थिति में न हो, उस सरकार को बजट नहीं, स्वेतपत्र जारी कर प्रदेश की वास्तविक स्थिति जनता और विधानसभा में रखनी चाहिए। माकपा नेता ने कहा है कि ज़ब प्रदेश पर कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ हो गया है, तब 4.38 लाख करोड़ का बजट प्रदेश की स्थिति को बयान करने के लिए काफ़ी है द्य राज्य सरकार ने इस राशि का बड़ा हिस्सा भी प्रदेश के प्रयटक स्थलों, होटलों और प्राकृतिक संसाधनों को बेच कर जुटाने का प्रावधान किया गया है द्य पूर्वजों की सम्पति को बेच कर मौज मस्ती को प्रदेश का विकास नहीं, विनाश ही कहा जायेगा द्य यह बजट किसान, मजदूर, गांव, गरीब, महिला, छात्र और युवा विरोधी बजट है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम से बढ़ा आत्मविश्वास और मिला तकनीकी मार्गदर्शन

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़कर ग्राम कंचरी के कृषक मनोज साहू ने रागी उत्पादन में रचा नया कीर्तिमान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा के ग्राम कंचरी के प्रगतिशील कृषक मनोज साहू ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए इस वर्ष एक अभिनव पहल की है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (ऋयङ्कङ्ग) के अंतर्गत 0.5 हेक्टेयर भूमि में पहली बार रागी (मंडिया) की खेती कर क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश दिया है। यह प्रयास न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रहा है।

बीज उत्पादन कार्यक्रम से बढ़ा आत्मविश्वास और मिला तकनीकी मार्गदर्शन

श्री साहू ने अपनी रागी फसल का पंजीयन बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य बीज निगम में कराया। इससे उन्हें कृषि विभाग एवं बीज निगम के विशेषज्ञों का नियमित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक वैज्ञानिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया। बीज उत्पादन के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों, खेत निरीक्षण, पृथक्करण दूरी तथा शुद्धता के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने फसल की विशेष देखभाल की।इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन एवं रोग नियंत्रण के आधुनिक उपायों की जानकारी मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने पूरी लगन के साथ खेती को अपनाया।

वैज्ञानिक पद्धति से खेती, बेहतर उत्पादन की उम्मीद

मनोज साहू ने पारंपरिक पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक तरीके अपनाए, जिनमें शामिल हैं, प्रमाणित एवं अनुशंसित उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग, समय पर बुवाई एवं कतार पद्धति से रोपण, संतुलित एवं मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन, नियमित निराई-गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु समुचित एवं समयबद्ध उपाय 7 इन तकनीकों को अपनाने से फसल की वृद्धि अत्यंत संतोषजनक रही है। खेत में फसल की स्थिति हरी-भरी एवं स्वस्थ दिखाई दे रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी उपज प्राप्त होने की प्रबल संभावना है।

पोषण एवं बाजार दोनों दृष्टि से लाभकारी फसल

रागी (मंडिया) एक पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज है, जिसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बदलती खानपान आदतों और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ने के कारण बाजार में इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में रागी की खेती किसानों के लिए आय का बेहतर विकल्प बनकर उभर रही है। चूंकि श्री साहू की फसल बीज उत्पादन हेतु पंजीकृत है, इसलिए बीज निगम द्वारा सामान्य बाजार मूल्य की तुलना में अधिक दर मिलने की संभावना है। इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही, भविष्य में वे रागी की खेती का रकबा बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं।

अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण

मनोज साहू की यह पहल दर्शाती है कि यदि किसान शासन की योजनाओं का लाभ लेकर नई एवं वैकल्पिक फसलों को अपनाएं और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, तो वे कम लागत में अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। उनका यह प्रयोग ग्राम कंचरी सहित पूरे जिला बेमेतरा के किसानों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में सामने आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी उनके प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचार से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि पोषण सुरक्षा एवं फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रागी उत्पादन एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़कर मनोज साहू ने यह सिद्ध किया है कि नवाचार, वैज्ञानिक सोच और शासकीय योजनाओं का समुचित उपयोग किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उनकी सफलता निश्चित ही जिले में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।

संपादकीय

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का 'सुरक्षा कवच'

यह छिपी बात नहीं है कि जितने बड़े इलाके में अरावली की पहाड़ियां फैली हैं, वहां और उसके आसपास उसकी क्या अहमियत है। इसे सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि समूची पर्वत-शृंखला को एक जीवन-रेखा की तरह देखा जाता है।विडंबना यह है कि वहां खनन और अन्य गतिविधियों की वजह से पूरे क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव और उसके नुकसानों को देखते हुए जब अरावली के संरक्षण के लिए स्वर तेज हो रहे हैं, वैसे में भी सरकार को नई परियोजनाओं के असर पर विचार करना जरूरी नहीं लग रहा है।गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुरुग्राम और नूंह जिले में प्रस्तावित जंगल सफारी पर विस्तृत योजना जमा करना चाहती थी। हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि सफारी परियोजना की विस्तृत रपट में जरूरत की भूमि को दस हजार एकड़ से बदल कर तीन हजार तीन सौ एकड़ कर दिया गया है। मगर शीर्ष अदालत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया और कहा कि जब तक विशेषज्ञ अरावली क्षेत्र की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक किसी को भी अरावली को छूने नहीं दिया जाएगा और कोई भी विकास या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी।गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्तूबर में हरियाणा सरकार की प्रस्तावित 'अरावली जू सफारी' परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार का कहना था कि इस परियोजना के तहत विश्व की सबसे बड़ी सफारी तैयार की जाएगी, जिसमें बाघ, पक्षी, सरीसृप और तितलियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए जाने थे। मगर भारतीय वन सेवा के पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों और एक संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहले ही संकट का सामना कर रही अरावली पर्वत-शृंखला के लिए यह परियोजना विनाशकारी साबित होगी। यह समझना मुश्किल है कि 'जू सफारी' बनाने या ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को जहां समूचे अरावली क्षेत्र के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, पर्यावरणविद् इसके लिए चेताते रहे हैं, उस इलाके में अरावली के परिभाषित होने तक रुकना क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा है।जिस पहलू को सरकार को खुद समझना चाहिए, उसके लिए शीर्ष अदालत को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक जैसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में विशेषज्ञों की रपट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में खनन के नए पट्टे देने पर रोक लगा दी थी।चार राज्यों और कई सौ किलोमीटर के क्षेत्र में फैली अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत शृंखलाओं में एक है और यह थार मरुस्थल को पूर्व यानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलने से रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है।

बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ी है। लगभग दो दशकों के लंबे अंतराल के बाद यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंचते हैं, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा परिवर्तन का संकेत होगा। 299 सीटों में से 212 पर विजय का दावा इस बात का प्रमाण है कि मतदाता लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता, अंतरिम व्यवस्थाओं और वैचारिक ध्रुवीकरण से बाहर निकलकर एक निर्णायक जनादेश देना चाहता है। छात्र आंदोलन से उपजी नेशनल सिटीजन पार्टी का मात्र छह सीटों पर सिमटना भी इस तथ्य को पुष्ट करता है कि जनभावना प्रयोगधर्मिता से आगे बढ़कर स्थायित्व की ओर झुक रही है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की वैचारिक क्रांति

(ललित गर्ग)

लगभग अठारह महीने से चल रही अंतरिम व्यवस्था के अवसान के साथ बांग्लादेश एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहा है, पर प्रश्न यह है कि यह अध्याय उदार लोकतंत्र का होगा या किसी नए प्रकार के वैचारिक वर्चस्व का?बांग्लादेश का इतिहास संघर्ष, त्याग और पहचान की जिजीविषा से निर्मित हुआ है। 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की निर्णायक भूमिका केवल सैन्य सहायता तक सीमित नहीं थी, वह सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग का भी प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, कट्टरवादी विमर्श और बाहरी प्रभावों ने उस ऐतिहासिक आत्मीयता पर धुंध डालने का प्रयास किया। अंतरिम सरकार के दौरान जिस प्रकार वैचारिक कठोरता और प्रशासनिक असमंजस दिखा, उसने अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित किया। ऐसे समय में स्पष्ट जनादेश को स्थिरता का अवसर माना जा सकता है, बशर्ते सत्ता इसे प्रतिशोध का माध्यम न बनाए, बल्कि पुनर्निर्माण का औजार बनाए।

तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना होगी। बांग्लादेश का सामाजिक ढांचा बहुलतावादी है, वहां अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सम्मान केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की कसौटी है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से दूरी बनाकर विकासोन्मुखी एजेंडा अपनाती है, तो वह न केवल आंतरिक स्थिरता ला सकती है, बल्कि दक्षिण एशिया में एक सकारात्मक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकती है। पर यदि चुनावी विजय को वैचारिक वर्चस्व के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो यह जनादेश अवसर से अधिक संकट में बदल सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश ने पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वस्त्र उद्योग, निर्यात वृद्धि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उसने मिसाल कायम की। किंतु राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेशकों के विश्वास को झटका दिया। अब नई सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह आर्थिक सुधारों को गति दे, रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे और विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए। विकास की नई गंगा तभी बहेगी जब शासन पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी होगा। केवल नारे या राष्ट्रवाद की तीखी ध्वनियां आर्थिक संकट का समाधान नहीं बन सकतीं।

भारत-बांग्लादेश संबंध इस चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता और आर्थिक परस्परता है। सीमा प्रबंधन, जल बंटवारा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे परस्पर विश्वास से ही सुलझ सकते हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती निकटता और भारत के प्रति संदेहपूर्ण बयानबाजी ने संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा किया। यदि नई सरकार क्षेत्रीय संतुलन की नीति अपनाते हुए भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संवाद पुनः स्थापित करती है, तो यह दोनों देशों के हित में होगा। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उस ऐतिहासिक साझेदारी को भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक आधार पर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब केवल द्विपक्षीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। चीन की बढ़ती उपस्थिति, अमेरिका की रणनीतिक रुचि और पाकिस्तान की पारंपरिक भूमिका-इन सबके बीच बांग्लादेश को संतुलित कूटनीति अपनानी होगी। यदि नई सरकार वैचारिक आग्रहों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखती है, तो वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक परिपक्व भूमिका निभा सकती है। परंतु यदि विदेश नीति घरेलू राजनीति का विस्तार बन गई, तो अस्थिरता का चक्र फिर दोहराया जा सकता है।

इस चुनाव का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बांग्लादेश का मतदाता अब निर्णायकता चाहता है। लंबे समय तक आंदोलन, विरोध और अंतरिम प्रयोगों से थका समाज स्थिर शासन की आकांक्षा रखता है। किंतु स्थिरता केवल बहुमत से नहीं आतीय वह संस्थाओं की मजबूती, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वायत्तता से आती है। नई सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं, बल्कि असहमति को सम्मान देने की संस्कृति का नाम है। यदि विपक्ष को हाशिये पर धकेला गया या आलोचना को देशविरोध का रूप दिया गया, तो लोकतांत्रिक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी।

बांग्लादेश के लिए यह क्षण आत्ममंथन का भी है। क्या वह अपनी पहचान को केवल धार्मिक राष्ट्रवाद तक सीमित करेगा, या भाषा, संस्कृति और बहुलता की उस विरासत को आगे बढ़ाएगा जिसने उसे जन्म दिया? मुक्ति संग्राम की मूल भावना सामाजिक न्याय और समान अवसर की थी। यदि नई सत्ता उस भावना को पुनर्जीवित करती है, तो यह जनादेश ऐतिहासिक सिद्ध होगा। अन्यथा यह अवसर भी इतिहास की एक और चूकी हुई संभावना बन सकता है।

भारत की दृष्टि से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली को प्रतिक्रिया में उतावलापन नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीतिक परिपक्वता दिखानी होगी। पड़ोसी देश की संप्रभुता और जनादेश का सम्मान करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाना ही दीर्घकालिक हित में है। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दों पर सख्ती के साथ-साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संवाद को भी सुदृढ़ करना होगा। संबंधों में भावनात्मकता के बजाय व्यावहारिकता और पारस्परिक सम्मान की नींव आवश्यक है।

अंततः यह चुनाव बांग्लादेश के लिए निर्णायक इसलिए है क्योंकि यह केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि शासन की शैली और राष्ट्रीय दिशा तय करने का क्षण है। यदि नई सरकार कट्टरवाद से मुक्त, समावेशी और विकासोन्मुखी नीति अपनाती है, तो वह बांग्लादेश को स्थिरता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर कर सकती है। परंतु यदि वह अतीत की कटु स्मृतियों और वैचारिक आग्रहों में उलझी रही, तो जनादेश की सार्थकता संदिग्ध हो जाएगी। बांग्लादेश को अब नई संभावनाओं, नई सोच और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। यही इस चुनाव का संदेश है और यही उसकी वास्तविक परीक्षा भी। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

जेन-जेड की डिजिटल दुनिया, ताकत या कमजोरी

(सुरेश सेठ)

इस समय बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल दुनिया से प्रभावित इस शक्ति को अगर सही दिशा नहीं मिली, तो इससे उनका ही नुकसान हो सकता है। दुनियाभर में युवाओं की नई पौध कहीं अधिक प्रखर और त्वरित कदमों से आगे बढ़ने वाली पीढ़ी है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर की इस पीढ़ी को आजकल 'जेन-जेड' कहा जा रहा है। यही वह नई युवा शक्ति है, जो अपने-अपने देशों में अन्याय और विसंगतियों के विरुद्ध खड़ी हो रही है। कुछ समय पहले पूरी दुनिया ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उन प्रदर्शनों को देखा, जिनमें हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। उस समय ऐसा लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा। जो विसंगतियां हैं, अब वे खत्म होंगी। चाहे वह भ्रष्टाचार हो या नेताओं का परिवारवाद या फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और इन देशों में ढर्रा वही रहा, जो पहले था। सत्ता परिवर्तनों के बावजूद कोई खास बदलाव सामने नहीं आया।

नई युवा शक्ति का असमानता और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना उन देशों के लिए असरदार हो सकता है, जहां स्थिति सचमुच बेहद खराब है और जहां अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है। मगर दिक्कत यह है कि कृत्रिम मेधा और सोशल मीडिया से प्रभावित यह पीढ़ी तत्काल सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहती है। मगर सच तो यह है कि अचानक सड़कों पर उतर जाने से रातों-रात व्यवस्था नहीं बदल जाती। यह पीढ़ी अपनी ताकत का धैर्य और सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करे, तो दुनिया में जो बदलाव वे चाहते हैं, वह संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस पीढ़ी की सार्थकता और उसकी ताकत पर दुनिया का भरोसा कायम हो सकता है। मगर अभी ऐसा हुआ नहीं है। इस समय बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल दुनिया से प्रभावित इस शक्ति को अगर सही दिशा नहीं मिली, तो इससे उनका ही नुकसान हो सकता है। भारत में इस युवा पीढ़ी को सार्थक निवेश के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश इनका साथ लेकर प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होना चाहता है। मगर, ये उम्मीदें आगे कितनी सच होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। देश की युवा आबादी कार्ययोग्य है, लेकिन उन्हें काम देने की बजाय अनुकंपा पर जीने की राह दिखाई जा रही है। अगर वे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए दूसरे देशों की ओर पलायन करते हैं, तो वहां से उन्हें किस तरह से स्वदेश वापस भेजा गया है, इसे सभी ने देखा है। अपने देश में तो रोजगार की गुंजाइश बढ़ नहीं रही, ऐसे में युवा करे, तो क्या करें। वहीं इनके सही राह से भटक जाने का जो जोखिम है, इसे कौन समझेगा। युवा देश की अमूल्य निधि होते हैं। उनके प्रखर और विकासोन्मुख होने की बात कही जाती है। मगर अभी दुनिया के कई देशों में अनुसंधान का निष्कर्ष यह बताता है कि आधुनिक तकनीक अपनाने वाली इस पीढ़ी की मेधा शक्ति पिछली पीढ़ी से कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका कारण यह बताया जाता है कि 'जेन-जेड' कहलाने वाली यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है। स्वयं खोज करने या अनुसंधान करने की बजाय उन्हें पहले से तैयार सब चीजें चाहिए। कई बार उनमें मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती। उनमें कितनी संभावनाएं हैं, यह सामने आना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि भारत कृत्रिम मेधा और डिजिटल दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह साफ है कि नई पीढ़ी मेधा और स्मृति के मामले में पिछली पीढ़ी जितनी भी नहीं दिखाई देती है। देश में तकनीक के अधिक इस्तेमाल के कारण किसी में स्वयं खोज करने की पहल नहीं दिखाई देती। शोध विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले पचास- साठ साल में जैसे-जैसे भारत सहित पूरी दुनिया में तकनीक का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा है, बच्चों में सीखने की क्षमता घट गई है। मगर जो बच्चे प्रौद्योगिकी का कम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनके परिणाम उन बच्चों से बेहतर हैं, जो डिजिटल सुविधा पर निर्भर हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कृत्रिम मेधा का बोलबाला हो गया है। सब जगह कागज रहित कार्य संस्कृति विकसित होने लगी है। दूसरी ओर इसी नई तकनीक का नतीजा है कि अब पुस्तकों के जरिए कम और स्मार्ट फोन, लैपटाप एवं कंप्यूटर पर शिक्षा देने का चलन बढ़ रहा है।

वायु प्रदूषण से जुड़ी मौतें, जब स्वास्थ्य का असर दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय आंकड़े पीछे रह जाते हैं

उत्तर भारत के शहरों, विशेषकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव अब किसी से छिपा नहीं है। बढ़ता वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल बनता जा रहा है। वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और फसलों के अवशेष जलाना इसके प्रमुख स्रोत हैं, जो फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग और मस्तिष्काघात जैसी जानलेवा बीमारियों का जोखिम बढ़ा देते हैं। यह समस्या न केवल स्वास्थ्य, बल्कि आर्थिक उत्पादकता और कृषि को भी प्रभावित कर रही है। मगर सवाल यह है कि भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को दर्ज करने के लिए क्या मृत्यु प्रमाणपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है और यदि ऐसा है, तो इसके लिए माकूल व्यवस्था का अभाव क्यों है?

(रोहन सिंह)

यह प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का कहना है कि देश में ऐसा कोई राष्ट्र-स्तरीय डेटा उपलब्ध नहीं है, जो बीमारियों या मौतों को वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ता हो।

किसी भी महामारी से निपटने के विज्ञान में 'एक्सपोजर-रिस्पॉन्स मॉडल', अतिरिक्त मृत्यु दर का अनुमान और जनसंख्या-स्तरीय जोखिम आकलन जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। भारत स्वयं तंबाकू-संबंधी कैंसर और व्यावसायिक जोखिमों से जुड़ी बीमारियों के आकलन में इन तरीकों को स्वीकार करता है। यदि वायु प्रदूषण कोई वायरस होता, तो संभवतः भारत अब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका होता। पिछले वर्ष सरकार की ओर से राज्यसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में कहा गया था कि देश में ऐसा कोई निर्णायक राष्ट्र-स्तरीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जो मौतों या बीमारियों को केवल वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जोड़ता हो।

वर्ष 2007 में भी सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आईजीआईडीआर के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि घर के भीतर वायु प्रदूषण के कारण लगभग 4.07 लाख भारतीयों की समय से पहले मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा था कि इन मौतों और वायु प्रदूषण के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है।

इस संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि देशव्यापी मृत्यु प्रमाणपत्रों के अभाव को तकनीकी रूप से सही ठहराया जा सकता है, लेकिन यह चिकित्सकीय सत्य को पूरी तरह नहीं दर्शाता। सार्वजनिक स्वास्थ्य में जिम्मेदारी केवल एक कारण वाले मृत्यु प्रमाणपत्रों से नहीं मापी जा सकती। अधिकांश प्रदूषण-जनित मौतें हृदय और श्वसन संबंधी रोगों के बढ़ने के कारण होती हैं, जहां वायु प्रदूषण एक जोखिम कारक के रूप में काम करता है, न कि अकेले कारण के रूप में। सरकार का तर्क संभवतः तकनीकी पहलू पर आधारित है - अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य रिकार्ड या ऐसे गहन अध्ययनों का अभाव, जिनमें प्रत्येक मौत को स्पष्ट रूप से 'वायु प्रदूषण-जनित' के रूप में दर्ज किया गया हो।

यह कहना कि 'निर्णायक राष्ट्रीय डेटा' उपलब्ध नहीं है, कुछ हद तक तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वायु प्रदूषण मौतों का कारण नहीं बन रहा।

उत्तर भारत के शहरों, विशेषकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव अब किसी से छिपा नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय और अनेक अध्ययनों ने बार-बार यह दिखाया है कि सूक्ष्म कणों से होने वाला वायु प्रदूषण मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालता है। लांसेट पत्रिका में प्रकाशित 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी' के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 में दस लाख से अधिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुईं, जो देश में कुल मौतों का लगभग 18 प्रतिशत है।

अध्ययन से यह भी पता चला कि वर्ष 1990 से 2019 के बीच सूक्ष्म कणों से होने वाली मृत्यु दर में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई। चिंताजनक तथ्य यह है कि वायु प्रदूषण से होने वाला नुकसान बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के एक विश्लेषण से पता चलता है कि विषाक्त वायु भ्रूण में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे समय से पहले जन्म, नवजात का कम वजन, फेफड़ों के विकास में रुकावट और बाल्यावस्था में दीर्घकालिक श्वसन समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है।

पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकीकरण, वाहनों की संख्या में तेजी और कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पर्यावरण को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि इसके विषैले तत्व अब हर सांस और भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। नीति-प्रतिक्रियाएं अधिकांशतः अल्पकालिक रही हैं, जबकि यह स्वास्थ्य संकट दीर्घकालिक और अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव डालता है।

हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली के छह प्रमुख सरकारी अस्पतालों के रिकार्ड का हवाला देते हुए बताया गया कि पिछले तीन वर्षों में इन अस्पतालों में दो लाख से अधिक गंभीर श्वसन रोगों के मामले दर्ज किए गए, जिन्हें वायु प्रदूषण से जोड़ा गया। बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील समूहों में अस्थमा, सांस फूलने और श्वसन संबंधी समस्याओं के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि यह दर्शाती है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल सांख्यिकीय अनुमान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चिकित्सकीय वास्तविकता बन चुका है।

विभिन्न शोध यह भी संकेत देते हैं कि वायु प्रदूषण केवल श्वसन रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोगजनकों के प्रसार को भी प्रभावित कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में दिल्ली के कुछ घनी आबादी वाले इलाकों की हवा में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी जीवाणुओं की मौजूदगी पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि सूक्ष्म कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) जीवाणुओं के लिए वाहक की तरह काम कर सकते हैं, जिससे वे हवा में लंबे समय तक बने रहते हैं और मानव शरीर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है।

यह एक ऐसा पहलू है, जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य नीति को अब भी अलग-अलग खांचों में देखने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। स्वास्थ्य आपातकाल को केवल डेटा की श्रेणियों पर तकनीकी बहस तक सीमित नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में हर दिन वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव देखे जा रहे हैं, लेकिन इन्हें आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य संकट नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह की मौतें 'वायु प्रदूषण-जनित' की स्पष्ट श्रेणी में दर्ज नहीं होतीं। यह चक्रीय तर्क डेटा अंतराल के माध्यम से जवाबदेही में देरी करता है। लाखों भारतीयों के लिए यह संकट रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है - बच्चे और युवा सर्दियों की धुंध भरी हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं, बुजुर्ग मरीजों से अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और श्रमिक वर्ग विषाक्त हवा में बिना पर्याप्त सुरक्षा के काम करने को मजबूर है।

ऐसे में भारत को वायु प्रदूषण को केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का एक संरचनात्मक निर्धारक मानना चाहिए। राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों में वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकीकृत करने, आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने और नीति विमर्श में प्रदूषण-जनित मृत्यु दर को स्पष्ट मान्यता देने की आवश्यकता है। ये केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी हैं, जो स्वच्छ हवा में सांस लेने के नागरिक अधिकार से जुड़ी हुई हैं।

संक्षिप्त समाचार

सैमसंग जल्द पेश करेगा सहज गैलेक्सी कैमरा अनुभव; अब कंटेंट बनाना होगा और भी आसान

दिन में खिंची गई फोटो को कुछ ही सेकंड में 'नाइट मोड' जैसा लुक देना हो, तस्वीर से गायब हिस्सों को वापस जोड़ना हो (जैसे केक का कटा हुआ हिस्सा ठीक करना), या कई तस्वीरों को मिलाकर एक शानदार इमेज बनानी हो—अब यह सब बेहद आसान होने वाला है। पहले इस तरह की एडिटिंग के लिए पेशेवर कौशल (प्रोफेशनल स्किल्स) या घंटों की मेहनत की जरूरत होती थी। लेकिन अब, आप अपने गैलेक्सी फोन पर बस कुछ शब्दों में अपनी जरूरत बताकर मिनटों में यह काम कर सकेंगे। यह गैलेक्सी कैमरा का अगला बड़ा विकास है—जो अब तक के सबसे ब्राइट गैलेक्सी कैमरा सिस्टम पर आधारित एक 'एंड-टू-एंड' अनुभव प्रदान करेगा। आज के दौर में मोबाइल कैमरे सिर्फ फोटो लेने तक सीमित नहीं रह गए हैं। लेटेस्ट गैलेक्सी एआई तकनीक अब फोटो खींचने, एडिट करने और शेयर करने की उन्नत क्षमताओं को एक ही 'सहज प्लेटफॉर्म' (इंट्यूटिव प?लेफॉर्म) पर लेकर आएगी। इसका परिणाम एक निर्बाध अनुभव और अधिक सुगम रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में सामने आएगा—जिससे यूज़र्स को अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने या जटिल टूल्स को समझने की जरूरत नहीं होगी। इससे कंटेंट बनाना पहले से कहीं अधिक तेज, सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। इस बदलाव के मूल में यह सोच है कि—रचनात्मकता किसी तकनीकी जानकारी या अनुभव की मोहताज नहीं होनी चाहिए। शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक, गैलेक्सी कैमरा ने मोबाइल फोटोग्राफी की संभावनाओं कोपुनर्परिभाषित किया है। अब कोई भी यूज़र आसानी से सिनेमैटिक वीडियो बना सकता है, रात के आसमान में तारों की गति को कैप्चर कर सकता है या कम रोशनी में भी बारीक विवरणों वाली तस्वीरें ले सकता है। इसके अलावा, आसान और प्राकृतिक कमांड की सुविधा के कारण एडिटिंग अब उतनी ही सरल है, जितना कि अपनी पसंद को शब्दों में बयां करना। तो, अब तक के सबसे आसान और यूज़र-फ्रेंडली गैलेक्सी कैमरा अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। इसका खुलासा अगले हफ्ते 'गैलेक्सी अनपैक्डफरवरी 2026' में किया जाएगा।

एशियन पेंट्स ने एक दमदार क्रिकेट एंथम के साथ किया क्रिकेट के रंगों को सजीव

रायपुर: भारत में क्रिकेट महज़ एक खेल नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह लोगों को गौरव, उम्मीद और उत्साह के साथ एकजुट रखता है। एकजुटता की इसी भावना के मद्देनजर एशियन पेंट्स ने लॉन्च किया है एशियन पेंट्स रंग दे इंडिया क्रिकेट एंथम। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जो संगीत के ज़रिए उन रंगों, भावनाओं और एकता की खुशियां मनाती है जिसे क्रिकेट हर भारतीय घर में भरता है। घर मिनी स्टेडियम में बदल जाते हैं और बालकनियों नारों से गूंज उठती हैं। यह एंथम मैच के दौरान की खुशी और जोश को दर्शाता है। यह हर पीढ़ी, वर्ग, क्षेत्र, भाषा और परंपरा के फैन्स को एक साथ बांधता है। एशियन पेंट्स और क्रिकेट, दोनों ही भारत के पलों और यादों में रंग भरते हैं। साथ मिलकर वे एक मजबूत भावनात्मक लगाव बढ़ाते हैं जो 1.4 अरब दिलों को एक साथ जोड़ता है। एशियन पेंट्स ने रंगों के ज़रिए और फैन्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ होने वाले घरेलू क्रिकेट के आधिकारिक कलर पार्टनर के रूप में अपने जुड़ाव को लगातार मज़बूत किया है। यह एंथम ब्रांड के इस विश्वास को दर्शाता है कि रंग भावनाओं की अभिव्यक्ति है और एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को करीब लाती है। रंग दे - मोहे जीत के रंग में रंग दे की धुन क्रिकेट की उस भावना, रंग और रोमांच को एक साथ पिरोती है, जिसे एशियन पेंट्स सेलिब्रेट करता है। ऊर्जा से भरपूर यह एंथम सुनने के साथ-साथ महसूस करने के लिए बनाया गया है। यह आकर्षक, उत्साहवर्धक और गर्व से भरा है, ठीक वैसे ही जैसे मैच के दौरान भावनाएं होती हैं। इसका संगीत समीर उद्दीन ने तैयार किया है और इसे सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी ने गाया है। उनकी दमदार और जोशीली आवाज़ें एंथम को यादगार बनाती हैं। यह एक ऐसा एंथम है जिसे फैन्स मैच के दौरान गुनगुनाएंगे, मैच देखने के दौरान बजाएंगे और मैच खत्म होने के काफी समय बाद भी याद रखेंगे। इस तरह से यह भारत के क्रिकेट सेलिब्रेशंस का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। यह चलचित्र उन विशेष क्षणों, परंपराओं और यादों को दर्शाती है, जो भारत में क्रिकेट को जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। यह देश के हर कोने से क्रिकेट फैन्स को सेलिब्रेट करती है। यह दिखाती है कि कैसे क्रिकेट क्षेत्र, उम्र और पृष्ठभूमि की सीमाओं को पार करते हुए लोगों को आपस में जोड़ता है। क्रिएटिव पार्टनर किनेक्ट के साथ मिलकर तैयार किया गया यह अभियान एक सामान्य खेल साझेदारी से कहीं आगे बढ़कर है। यह भारत की क्रिकेट भावना का उत्सव बन जाता है, जिसका उद्देश्य फैन्स के घरों और दिलों में बसना है। इस अभियान के बारे में एशियन पेंट्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमित सिंगल ने कहा, क्रिकेट में यह अनोखी और मज़बूत क्षमता है कि वो क्षेत्रों और पीढ़ियों से परे पूरे भारत को एकजुट कर सकता है।

जनदर्शन में कलेक्टर अग्रवाल ने सुनी लोगों की समस्याएं

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियाद सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। लोगों ने जनदर्शन में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हित से जुड़े विषयों को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवेदन दिया। नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे और सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने कलेक्टर से मिलकर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। जनदर्शन में आज बोदरी तहसील के ग्राम बोडसरा के छात्र दीपेश कुमार ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को लेकर कलेक्टर से सुधार की मांग की है। आवेदक का कहना है कि पुराने मिसल रिकॉर्ड में नाम की गलती के कारण उसका जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। त्रुटि के कारण राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े आवश्यक दस्तावेज नहीं बन पा रहे हैं, जिससे उसे शैक्षणिक और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने मामले को एसडीओ बिल्हा को सौंपा। कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने शासकीय तालाब के आने जाने के निस्तारी रास्ते पर सुखराम यादव द्वारा किये गये अवैध निर्माण कार्य को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम तेंदुवा के सुखराम यादव द्वारा निस्तारी रास्ते पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कर लिया गया है। जिससे ग्रामीणों को तालाब आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम को उक्त प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है। नहरपारा लिटिया के कैलाश प्रसाद साहू ने कलेक्टर से मुलाकात कर किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान करने गुहार लगाई। मामले को उप संचालक कृषि देखेंगे। शहर के वार्ड क्रमांक 36 बसंत भाई पटेल नगर के वासियों ने वार्ड में सीसी रोड, नाली, बिजली पोल एवं पानी पाईप लाईन लगाने की मांग की है। वार्ड वासियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कच्चे सड़क की वजह से पानी भराव एवं गदंगी की स्थिति निर्मित हो जाती है। जिससे स्कूली बच्चों सहित आमजनों को भी काफी परेशानियां होती है। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम को इस पर आवश्यक कार्यवाही करने कहा। सकरी तहसील के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कोपरा में तालाब निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए खसरा नंबर 81 और 82 की जमीन ग्राम सभा से स्वीकृत है। कुछ लोगों ने इस प्रस्तावित जमीन पर खेत बनाना शुरू कर दिया है और ट्रैक्टर से लगातार जुताई का काम जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सरपंच द्वारा इस कार्य को रुकवाया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसी जमीन पर खेती शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि संबंधित लोगों द्वारा किए जा रहे कब्जे और खेती के कार्य को तुरंत रोका जाए तथा प्रस्तावित तालाब की जमीन को सुरक्षित रखा जाए। कलेक्टर ने एसडीओ तखतपुर को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में राजस्व अभिलेखों में नाम सुधार, पुराने मिसल अभिलेख में त्रुटि संशोधन तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए। कुछ आवेदकों ने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने, किसान सम्मान निधि नहीं मिलने तथा बैंक एवं वित्तीय संस्था से संबंधित बकाया भुगतान की समस्याएं भी रखीं। इसके अलावा दुकान का जप्त सामान या राशि वापस दिलाने एवं आवास ऋण से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हुई।

शासकीय स्कूल टेकर को सिद्धा फाउंडेशन ने दिये छह पंखे भेंट..

परीक्षा को सदैव तनाव मुक्त देवें- श्री करियारे

बिलासपुर। शासकीय हाई स्कूल टेकर को सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा के द्वारा विद्यालय को 6 पंखे भेंट किए गए। इस अवसर पर राम गोपाल करियारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर मुख्य अतिथि के रूप में बतौर उपस्थित रहे। इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा जीवन की हरेक घटना में किसी-न-किसी रूप से आपको लाभ ही होता है। परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से होने वाले लाभ के बारे में ही सदैव सोचिए। अर्थात भूतकाल में की हुई ग़लतियों का पश्चाताप न करें तथा भविष्य की चिन्ता न करें। वर्तमान को सफल बनाने के लिये पूरा ध्यान परीक्षा में दीजिये। आज का ही दिन आपके हाथ में है। आज आप रचनात्मक कार्य करेंगे तो कल की ग़लतियाँ मिट जायेंगी और भविष्य में अवश्य लाभ होगा। शिक्षा जगत के प्रसिद्ध राम दत्त गौरहा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपने बच्चों को आगामी परीक्षा के लिए तनाव न लेने व पढ़ाई का आनंद लेने को कहा। उन्होंने बच्चों को याद रखने की युक्तियां बताई व शुभकामनाएं भी दी। हाई स्कूल टेकर प्राचार्य श्रीमती नसीम बेगम ने सभी अभ्यागतों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा, सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह, श्रीमती रमैया मैडम ,शिक्षा जगत के राम दत्त गौरहा, प्रधान पाठक आशुतोष तिवारी, व्याख्याता अर्जुन सोनवानी, श्रीमती रेवती शर्मा, श्रीमती आशा पटेल, राम कश्यप, अरविंद गिरी गोसाई तथा मिडिल और हाई स्कूल के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स फैक्ट्री पर आयकर का छापा

बिलासपुर। बिलासपुर जिले में आयकर विभाग ने सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री पर तड़के छापामार कार्रवाई की। यह कंपनी ष्टशष्ड्ड-ष्टशद्यड्ड ब्रांड के पेय पदार्थों का निर्माण करती है। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और संभावित टैक्स चोरी से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। प्रदीप अग्रवाल इसके मालिक बताए जा रहे हैं, जबकि बिलासपुर इकाई का संचालन नवनीत अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। आयकर विभाग की टीम ने फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ जारी है। जानकारी यह भी मिल रही है कि कंपनी से जुड़े देशभर के अन्य ठिकानों पर भी एक साथ कार्रवाई की जा रही है। रायपुर डिपो के अलावा उदयपुर बेवरेज (जबलपुर) और सुपीरियर ड्रिंक्स (नागपुर) में भी आयकर टीम की जांच चल रही है। फ्लिहाल फैक्ट्री के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी अंदर-बाहर आने की अनुमति सीमित कर दी गई है। आयकर अधिकारी आय, निवेश और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।

अटल बिहारी वाजपेयी विवि में सांस्कृतिक मूल्य एवं हिन्दी साहित्य पर विमर्श किया....

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पीएम-ऊषा के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय शिक्षण विभागमें सांस्कृतिक मूल्यों एवं हिन्दी साहित्य विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा, सम्मान समारोह एवं भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सृजनशीलता पर गंभीर विमर्श हुआ। विशेष सत्र में साहित्य सृजन एवं साहित्यिक योगदान के लिए प्रदेश की प्रतिष्ठित विभूतियों को सम्मानित किया गया। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी एवं मुख्य अतिथि शशांक शर्मा ने डॉ. विनय कुमार पाठक (वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग), डॉ. अजय पाठक (प्रतिष्ठित साहित्यकार), द्वारिका प्रसाद अग्रवाल (वरिष्ठ साहित्य सेवी) तथा सतीश जायसवाल (सुप्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्यकार) को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि शशांक शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य सृजन समाज को सही दिशा प्रदान करता है और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। उन्होंने विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति आचार्य वाजपेयी ने आयोजन को विश्वविद्यालय के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। भव्य कवि सम्मेलन में देश के ख्यात रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन में डॉ. विष्णु सक्सेना (गाजियाबाद), डॉ. सोनरूपा विशाल (बदायूँ), बलराम श्रीवास्तव (मैनपुरी), आचार्य देवेन्द्र देव एवं हिमांशु श्रोत्रिय (बरेली) की ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने सभागार में साहित्यिक वातावरण को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक यशवंत कुमार पटेल एवं सचिव गौरव साहू ने किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. तारणिश गौतम सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

संस्कृति विभाग द्वारा रायगढ़ घराने के स्तंभ पं. फ़िरतु महाराज की स्मृति में शास्त्रीय नृत्य संगीत समारोह

बिलासपुर। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की समृद्ध परंपरा को समर्पित दो दिवसीय भव्य शास्त्रीय नृत्य व संगीत समारोह का आयोजन 21 और 22 फरवरी को देवकीनंदन दीक्षित सभागार में किया जाएगा। संस्कृति विभाग के सहयोग से कला विकास केंद्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से होगा। यह आयोजन रायगढ़ घराने के स्तंभ एवं प्रख्यात नृत्याचार्य पंडित फ़िरतु महाराज जी की पावन स्मृति में समर्पित है। समारोह का उद्देश्य रायगढ़ घराने की गौरवशाली सांगीतिक एवं नृत्य परंपरा को जन-जन तक पहुँचाना है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना और कला विकास केंद्र की अध्यक्ष श्रीमती वासंती वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय कला से जोड़ना व वरिष्ठ एवं नवोदित कलाकारों को एक साझा मंच प्रदान करना है। दो दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक आयोजन में देश के प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक, वादक और नृत्य कलाकार अपनी उच्चकोटि की प्रस्तुतियों से श्रोताओं को सुर, ताल, लय और भाव की अद्भुत अनुभूति कराएँगे। उल्लेखनीय है कि पंडित फ़िरतु महाराज जी ने अपने जीवन को कला-साधना को समर्पित करते हुए रायगढ़ घराने की विशिष्ट शैली को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया। उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में अनेक शिष्यों ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। उनका योगदान केवल मंचीय प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा को जीवंत रखते हुए कला के संस्कारों को नई पीढ़ी में स्थापित किया। समारोह के दौरान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की विविध विधाओं की प्रस्तुतियाँ होंगी, जिनमें पारंपरिक बंदिशें, राग-रागिनियों की सुमधुर प्रस्तुति तथा भावप्रधान नृत्यांजलि विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजन स्थल को सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप सजाया जाएगा, जिससे श्रोताओं को एक सजीव और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में कला का आनंद मिल सके।आयोजक मंडल द्वारा शहरवासियों, कला-प्रेमियों, विद्यार्थियों एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस गरिमामय आयोजन को सफल बनाएँ और भारतीय शास्त्रीय कला की इस विरासत को आगे बढ़ाने में सहभागी बनें।

सीईओ जिला पंचायत ने जनदर्शन में सुनी आम नागरिको की समस्याएं

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण अंचलों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। जिसमें आमजनों ने विभिन्न विषयों से संबंधित अपनी समस्याएं और मांगें प्रस्तुत कीं। जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया तथा उनके शीघ्र एवं समयबद्ध निराकरण के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए।

रायपुर मंडल क्षेत्राधिकार के माननीय सांसदों के साथ महाप्रबंधक व रेल अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुआ

- बृजमोहन अग्रवाल,सांसद रायपुर की अध्यक्षता मे हुई बैठक
- यात्री सुविधाओं तथा रेल विकास से संबन्धित कार्यों पर बैठक में हुई चर्चा

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्रों के माननीय सांसदों की बैठक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के साथ आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को आयोजित की गई । मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रायपुर के सभागार में आयोजित यह बैठक सौहार्दपूर्ण तथा सहयोगात्मक माहौल में श्री बृजमोहन अग्रवाल माननीय सांसद रायपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक में श्री बृजमोहन अग्रवाल माननीय सांसद लोकसभा, रायपुर के अलावा श्री भोजराज नाग जी - माननीय सांसद- कांकेर लोकसभा, श्री महेश कश्यप जी - माननीय सांसद-बस्तर लोकसभा , श्रीमती रूपकुमारी चौधरी जी - माननीया सांसद-महासमुन्द लोकसभा, सहित श्री अरुण सिंह चौहान सांसद प्रतिनिधि (श्री तोखन साहू जी - राज्यमंत्री / आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार), श्री निलेश देशमुख सांसद प्रतिनिधि (श्री विजय बघेल सांसद / दुर्ग लोकसभा), सद्दाम सोलंकी सांसद प्रतिनिधि (श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी- माननीया सांसद/ राज्यसभा), श्री जसकरण सांसद प्रतिनिधि (श्रीमती रंजीत रंजन जी - माननीया सांसद/राज्य सभा) एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश मंडल रेल प्रबंधक रायपुर श्री दयानंद, मुख्यालय के प्रधान विभागाध्यक्ष एवं मंडल के अधिकारीगण उपस्थित रहे बैठक के प्रारंभ में महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्री तरुण प्रकाश ने उपस्थित सांसदों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी के मार्गदर्शन और बहुमूल्य सुझाव का लाभ हमें अपनी सेवाओं को और बेहतर करने में मिलेगा । बैठक में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल मे ट्रेनों के ठहराव, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चल रहे विकासात्मक कार्य, छत्तीसगढ़ को मिली नई ट्रेनों सहित माननीय सांसदों द्वारा दिए गए एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। यात्री सुविधाओं तथा विकासात्मक कार्यों, यात्री सुविधाओं,आधारभूत संरचना का विकास, गाड़ियों का क्षमता आवर्धन, यात्रियों के लिए टिकटिंग प्रणाली को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन आदि की विस्तृत जानकारी साझा की गई । माननीय सांसदों द्वारा मंडल में हो रहे विकास कार्यों, उपलब्ध यात्री सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया गया तथा अपने क्षेत्र से संबन्धित विभिन्न जन सरोकारों से संबन्धित मुद्दों के माध्यम से स्थानीय स्तर की समस्याओं तथा जनता की आकांक्षाएं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न स्टेशनों में यात्री सुविधा का विस्तार करने की आवश्कताओं से अवगत कराया तथा ट्रेनों के ठहराव, नई रेल सेवाओं पर सुझाव दिए। साथ ही बैठक में विभिन्न स्टेशनों में यात्री सुविधाओं तथा रेलवे विकास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई । महाप्रबंधक ने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं एवं अपेक्षाओं से रेल प्रशासन को अवगत कराने एवं विकासात्मक सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया ।

संक्षिप्त समाचार

चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले पटाखों की दुकान में विस्फोट, 8 लोगों की मौत

बीजिंग, एजेंसी। पूर्वी चीन में लूनर (न्यू ईयर) से ठीक पहले पटाखों की दुकान में हुए विस्फोट और

आग में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग मामूली रूप से झुलस गए। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। यह धमाका रविवार दोपहर जिआंगसू प्रांत के डोंगहाई काउंटी के एक गांव में हुआ। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, एक निवासी ने दुकान के पास गलत तरीके से पटाखे जलाए, जिससे विस्फोट हो गया। घटना के कारणों की जांच जारी है। सरकार के बयान में कहा गया कि दुकान के आसपास पटाखों को जलाना बैन है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लापरवाही से पटाखे जलाने के कारण आग भड़की और फिर विस्फोट हुआ। चीन में लूनर न्यू ईयर में पटाखे जलाना परंपरा का हिस्सा है। इसे बुरी शक्तियों को दूर भगाने का प्रतीक माना जाता है। हालांकि, हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण और सुरक्षा कारणों से कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले साल कुछ स्थानीय सरकारों ने इन प्रतिबंधों में ढील दी थी, जिससे बाजार में पटाखों की बिक्री बढ़ी। रविवार की घटना के बाद आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों से पटाखों के उत्पादन, परिवहन, बिक्री और उपयोग की निगरानी कड़ी करने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि दुकानों के आसपास पटाखे जलाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और स्थानीय प्रशासन जोखिम वाले जगहों की पहचान करे, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से त्यौहार मना सके। सुरक्षा चेतावनी जारी इस धमाके के बाद आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों को आग, पटाखों की बिक्री, उत्पादन, परिवहन और उपयोग की निगरानी बढ़ाने की चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा कि दुकानों के आसपास पटाखों का परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए और स्थानीय सरकारों से कहा कि वे सुरक्षा की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करें ताकि जनता सुरक्षित, मंगलमय और खुशहाल स्प्रिंग फेस्टिवल मना सके। गौरतलब है कि चीन में लूनर न्यू ईयर की रात को पटाखे जलाना एक प्राचीन परंपरा है। हाल के वर्षों में कई जगहों पर प्रदूषण को रोकने और सुरक्षा कारणों से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, पिछले साल कुछ सरकारों ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए पटाखों को कुछ क्षेत्रों में वापस अनुमति दी थी। इस वर्ष लूनर न्यू ईयर मंगलवार को मनाया जाएगा और यह चीनी ज्योतिष के अनुसार घोड़े के वर्ष की शुरुआत करेगा।

जमात-ए-इस्लामी के अमीर से मिले तारिक रहमान

ढाका, एजेंसी। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान ने जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान से मुलाकात कर चुनाव बाद हिंसा पर कार्रवाई का भरोसा दिया। 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी गठबंधन को 300 में से 212 सीटें मिलीं, जबकि जमात 77 सीटों के साथ प्रमुख विपक्ष बनकर उभरी। जमात ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित में सहयोग करेगी, पर सरकार से जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद संभालने की तैयारी के बीच यह मुलाकात राजनीतिक संतुलन का संकेत मानी जा रही है। पाकिस्तान के झेलम में पुलिस ने इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। घटना उनके कुरआन-ओ-सुन्नत रिसर्च अकादमी में हुई, जहां आरोपी ने कथित रूप से गला दबाने और पगड़ी उतारने की कोशिश की। पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 324 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। मिर्जा पहले भी हमलों और ईशनिंदा आरोपों का सामना कर चुके हैं तथा 2021 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। वह यूट्यूब पर लोकप्रिय धार्मिक व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बाद कहा कि वायु रक्षा के लिए मिसाइलें सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने अमेरिका और जर्मनी का समर्थन के लिए आभार जताया तथा जर्मनी के साथ संयुक्त ड्रोन उत्पादन लाइन शुरू होने की जानकारी दी।

चीन ने पहाड़ खोदकर बना डाले परमाणु ठिकाने

तस्वीरों में सामने आया ड्रैगन का खतरनाक इरादा, चीन की नई चाल का सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

न्यूयॉर्क , एजेंसी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियोस्पेशल की सैटलाइट तस्वीरों में चीन के खतरनाक इरादों का खुलासा हुआ है। चीन पहाड़ खोदकर परमाणु ठिकाने बना रहा है। कई मशीनें ऐक्टिव भी हो गई हैं।

चीन के सिचुआन की कुछ सैटलाइट तस्वीरों ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। 2022 से 2026 तक की सैटलाइट तस्वीरों के अध्ययन से पता चला है कि चीन सिचुआन प्रांत में गुप्त रूप से परमाणु हथियारों के ठिकाने बना चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2019 के बाद से चीन ने परमाणु हथियारों को लेकर अभियान तेज कर दिया है।

सिचुआन में जिटॉन्ग नाम की जगह पर घाटियों के बीच चीन ने बड़े-बड़े बंकर बनाए हैं। यहां पर पाइप का जाल बिछाया गया है। जानकारों का कहना है कि यहां पहाड़ों को खोदकर परमाणु अड्डे बनाए गए हैं। बता दें कि दुनियाभर में परमाणु हथियारों को लेकर तनाव पहल से ही कम नहीं है। इसी मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने-सामने खड़े हैं और अमेरिका सीधी धमकी दे रहा है कि अगर ईरान के सीथ डील नहीं हुई तो वह हमला कर देगा। दूसरी ओर चीन का यह परमाणु अभियान ना केवल भार बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से जारी तस्वीरों के मुताबिक चीन अपनी स्ट्रैटजिक पोजीशन को लगातार मजबूत करने में लगा है। अमेरिका ने 2020 में ही दावा किया था कि चीन गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है

कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका केसाथ न्यूक्लियर वेपन एग्रीमेंट करें। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्यिर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट खत् हो चुका हैऔर इसलिए चीन को भविष्य के समझौते का हिस्सा बनना चाहिए। पेंटागन के एक अनुमान के मुताबिक 2024 के आखिरी तक चीन के पास 500 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। वहीं 2030 तक उसाक लक्ष्य यह आंकड़ा 1 हजार तक पहुंचाने का है। हालांकि अभी चीन रूस और अमेरिका से बहुत पीछे है और अगले 10 साल में भी वह रूस की बराबरी नहीं कर सकता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। बीजिंग दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में पहाड़ों के अंदर गुप्त रूप से परमाणु हथियारों से जुड़ी सुविधाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में रविवार को बताया कि 2022 और 2026 के बीच ली गई उपग्रह तस्वीरों के भू-स्थानिक विश्लेषण से दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में गुप्त परमाणु हथियार सुविधाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का पता चला है।

भू-स्थानिक खुफिया विशेषज्ञ रेनी बाबियारज द्वारा साझा किए गए निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि 2019 से चीन के परमाणु निर्माण में तेजी आई है, जो देश की रणनीतिक क्षमताओं में एक अहम मोड़ है। सिचुआन में जिटोंग नाम की एक साइट पर इमेज से घाटी में नए बने बंकर और दीवारें दिखती हैं। उस जगह पर एक नए बने कॉम्प्लेक्स में बड़ा पाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बारे में एनालिस्ट्स का कहना है कि यह उन सुविधाओं से मेल खाता है, जो खतरनाक मटीरियल को हैंडल करती हैं। विश्लेषण में बताए गए एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि बंकरों का इस्तेमाल शायद उच्च-विस्फोटक परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। यह एक प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल केमिकल डेटोनेटर को रिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो एक वॉरहेड में न्यूक्लियर मटीरियल को कंप्रेस करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूर करने में जुटा है।

भारत के लिए क्यों है टेंशन

जानकारों का कहना है कि चीन के पास परमाणु हथियारों का बढ़ना भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी में एक अधिकारी का कहना है कि यह ट्रेंड काफी चिंताजनक है। जिटोंक और पिंगटोंग में निर्माण कार्य बहुत तेज है। यहां एक नया कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। जिटोंग में बंकर और हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। इसमें धमाका करने पर शॉक वेव दूर तक असर नहीं करती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के असली इरादों का अभी पता नहीं चल पाया है। वह सेना में बड़े स्तर पर सुधार करना चाहता है और परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बनना चाहता है।

अमेरिका से बातचीत में ईरान ने ऊर्जा, विमान सौदों का रखा प्रस्ताव

तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान आर्थिक सहयोग के कई बड़े प्रस्ताव लेकर आया है

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ ऐसा परमाणु समझौता करना चाहता है जिससे दोनों देशों को आर्थिक फायदा हो। एक ईरानी राजनयिक ने रविवार को बताया कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाले दूसरे दौर की बातचीत से पहले ईरान आर्थिक सहयोग के कई बड़े प्रस्ताव लेकर आया है।

ईरान और अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में अपने दशकों पुराने परमाणु विवाद को सुलझाने के लिए फिर से बातचीत शुरू की है। उद्देश्य है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे तनाव को कम करना और किसी नए सैन्य टकराव से बचना।

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका ने क्षेत्र में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो लंबा सैन्य अभियान भी चलाया जा सकता है। रुबियो ने कहा, अब तक कोई भी ईरान के साथ सफल समझौता नहीं कर पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ईरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो

वह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। लेकिन रविवार को उसका रुख थोड़ा नरम दिखाई दिया। विदेश मंत्रालय में आर्थिक कूटनीति के उप-निदेशक हमीद गनबरी ने कहा कि समझौते को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए जरूरी है कि अमेरिका को भी जल्दी और बड़े आर्थिक फायदे मिलें। उन्होंने बताया कि तेल और गैस के साझा क्षेत्र, संयुक्त खनन निवेश और यहां तक कि विमान खरीद जैसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल हैं। उनका कहना है कि साल 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं मिला था। 2015 का समझौता और 2018 में अमेरिका का बाहर होना साल 2015 में ईरान ने कई विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत उसने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं लगाईं और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी गई। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जिनेवा में होने वाली अहम बैठक सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं, मंगलवार को जिनेवा में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेगा।

खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था एपस्टीन!

वाशिंगटन, एजेंसी। यौन अपराधों के दोषी जेफ्री एपस्टीन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। इस बार सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या एपस्टीन, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था, खासकर पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक के कार्यकाल के दौरान। सरकारी अधिकारियों और पूर्व खुफिया प्रमुखों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया मंच ङ्क पर लिखा कि एपस्टीन और एहुद बराक की नजदीकी यह साबित नहीं करती कि एपस्टीन इजरायल के लिए काम करता था, बल्कि यह इसके ठीक उलट संकेत देती है। उन्होंने बराक पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह वर्षों से इजरायली लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 100 प्रतिशत निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि जेफ्री एपस्टीन का मोसाद या इजरायल से कोई लेना-देना नहीं था। उसने कभी मोसाद के लिए काम नहीं किया। पूर्व मोसाद प्रमुख योसी कोहेन ने भी कहा कि एपस्टीन का खुफिया एजेंसी से बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज जारी किए हैं। 30 जनवरी को जारी अंतिम दस्तावेज़ी खेप में कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए, लेकिन कहीं भी यह साबित नहीं होता कि एपस्टीन मोसाद का एजेंट था। इन दस्तावेजों में ईमेल, वित्तीय रिकॉर्ड और निजी संपर्कों का उल्लेख है, जिनकी जांच अब और तेज हो गई है। एहुद बराक ने स्वीकार किया कि उनकी एपस्टीन से मुलाकातें हुई थीं।

उइगर दमन पर चीन की घेराबंदी, एशिया से यूरोप तक बढ़ा वैश्विक विरोध

बीजिंग, एजेंसी। चीन द्वारा उइगर मुस्लिम समुदाय पर किए जा रहे दमन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने अपने साप्ताहिक ब्रीफ में बताया कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में राजनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक मोर्चों पर चीन की नीतियों को चुनौती दी जा रही है।

जापान में प्रधानमंत्री साने ताकाइची और उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की संसदीय जीत का वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने स्वागत किया है। ताकाइची पहले भी उइगर प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चुकी हैं और इस मुद्दे पर संसदीय स्तर पर समर्थन जताती रही हैं। इसके साथ ही उइगर मूल की सांसद एरी अरफिया के दोबारा चुने जाने को भी लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए सकारात्मक संकेत बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन उइगर तंगरितिाग महिला संघ ने फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में याचिका दायर कर रिटेल कंपनी से उन सप्लायर्स की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है, जिनका संबंध कथित तौर पर चीन के उइगर क्षेत्र में जबरन श्रम से है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक दासता कानूनों को और सख्त करने की बहस के बीच सामने आया है। जिनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उइगर अधिकार

कार्यकर्ता जुमरताय अर्किन ने कहा कि चीन का दमन अब अस्थायी अभियान नहीं बल्कि एक संस्थागत प्रणाली बन चुका है। उन्होंने परिवारों की जबरन जुदाई, श्रम स्थानांतरण और उइगर महिलाओं को निशाना बनाने की नीतियों पर चिंता जताई और सरकारों को बिना जवाबदेही के चीन से रिश्ते बहाल न करने की चेतावनी दी। मेक्सिको में आयोजित कार्यक्रम में उइगर कार्यकर्ता रुशन अब्बास ने कहा कि चीन की जबरन श्रम नीतियों का असर वैश्विक सप्लाई चेन तक पहुंच रहा है। उन्होंने अपनी बहन गुलशन अब्बास की कैद का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल व्यापार नहीं, बल्कि इंसानी पीड़ा से जुड़ा है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से पहले यूरोपीय देशों में चीन से संबंधों पर पुनर्विचार की चर्चा तेज है। वहीं हांगकांग में मीडिया उद्यमी जिमी लाई को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लंबी सजा दिए जाने के बाद नागरिक स्वतंत्रताओं के सिमटने पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। अधिकार समूहों का कहना है कि यह कार्रवाई चीन की दमनकारी पहुंच के विस्तार का संकेत है।

बहन और बेटी की लड़ाई में फंसा क्रूर तानाशाह!

13 साल की पुत्री को पावर देने की तैयारी में किम जोंग उन

प्योंगयांग/सियोल, एजेंसी। देश पर कंट्रोल करने की लड़ाई दोनों के बीच तेज हो सकती है। किम जू ऐ की उम्र महज 13 साल है और चर्चा है कि उसे 14 साल का होते ही किम जोंग उन की ओर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। उन की बहन भी खुद को एक पावर सेंटर मानती रही हैं। ऐसे में संभव है कि यह संघर्ष बढ़ सकता है।

दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक किम जोंग उन के परिवार में ही फिलहाल झगड़ा होता दिख रहा है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का कहना है कि किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ का नाम अगले नेता के तौर पर घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किम जोंग उन की बेटी का मुकाबला पावरफुल बुआ किम यो जोंग से हो सकता है। भविष्य में देश पर कंट्रोल करने की लड़ाई दोनों के बीच तेज हो सकती है। किम जू ऐ की उम्र महज 13 साल है और चर्चा है कि उसे 14 साल का होते ही किम जोंग उन की ओर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। उन की बहन भी खुद को एक पावर सेंटर मानती रही हैं। ऐसे में संभव है कि यह संघर्ष बढ़ सकता है। साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने बीते

सप्ताह बताया कि किम जू ऐ की उम्र 13 साल की हो गई हैं। अब उन्हें औपचारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। यह समय अहम है क्योंकि उत्तर कोरिया में इसी महीने एक बड़ा राजनीतिक आयोजन होने वाला है। इसमें किम जोंग उन बताएंगे कि देश के लिए भविष्य में क्या लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके अलावा वह देश की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी कुछ कदमों का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान किम जोंग उन की बेटी भी मंच पर हो सकती हैं। हाल ही में एक मीटिंग में वह अपने पिता का हाथ थामे हुए पहुंची थीं।

किम जू ऐ को किसी सार्वजनिक आयोजन में पहली बार नवंबर 2022 में देखा गया था। तब वह एक लॉन्ग रेंज मिसाइल के परीक्षण में पहुंची थीं। इसके बाद वह लगातार कई आयोजनों में पिता के साथ नजर आई हैं। उन्होंने हथियार फैक्ट्रियों के दौरे किए हैं तो वहीं सैन्य परेडों में भी हिस्सा लिया है। यही नहीं बीते साल सितंबर में वह चीन की राजधानी बीजिंग भी पहुंची थीं। आमतौर पर उत्तर कोरिया की राजनीति में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन पहली बार किम जोंग उन बेटी को कमान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें चीन ले जाया गया था ताकि उन्हें स्थापित किया जा सके।

ब्रिटिश उपप्रधानमंत्री बोले- भारत में एआई समिट से दुनिया को मिली नई दिशा, टेक सहयोग को मिलेगी नई रफ्तार

लंदन एजेंसी। ब्रिटेन के उपप्रधानमंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि भारत में सोमवार से शुरू हो रहा एआई इम्पैक्ट समिट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पूर्ण लाभों को हासिल करने का एक अहम वैश्विक अवसर है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार, इस शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन का फोकस इस बात पर रहेगा कि एआई किस तरह आर्थिक विकास को गति दे सकती है, नए रोजगार पैदा कर सकती है, सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बना सकती है और दुनिया भर के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती है।उपप्रधानमंत्री डेविड लैमी और ब्रिटेन के एआई मंत्री कनिष्क नारायण के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल यह रेखांकित करेगा कि एआई एक नवीनीकरण इंजन के रूप में कैसे काम कर सकती है। इसके जरिए डॉक्टरों को तेज और सटीक निदान, शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षण, स्थानीय प्रशासन को त्वरित सेवाएं और उद्योगों को अगली पीढ़ी के बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद मिल सकती है। शिखर सम्मेलन से पहले जारी बयान में लैमी ने कहा, यह समिट एक निर्णायक क्षण है, जहां हम अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर एआई की पूरी क्षमता और इसके लाभों को सामने लाने की दिशा तय कर सकते हैं।ब्रिटेन के विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत और ब्रिटेन को स्वाभाविक प्रौद्योगिकी साझेदार बताया है। विभाग ने कहा कि इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और विप्रो जैसी भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियां ब्रिटेन में तेजी से अपना विस्तार कर रही हैं। वेल्स से भारतीय मूल के पहले सांसद कनिष्क नारायण ने कहा,एआई हमारी पीढ़ी की निर्णायक तकनीक है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसके लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचें। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन एआइ के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिससे लोग अधिक सीख सकें, अधिक कमा सकें और अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर आकार दे सकें।

यूनुस के खिलाफ जांच आयोग बैठा सकती है रहमान सरकार

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद गठित मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में उछाल आया है। सरकार के मुखिया यूनुस की संपत्ति में एक साल में लगभग 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यूनुस की संपत्ति अब कुल साढ़े 12 करोड़ रुपए हो गई है, इसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए का उछाल आया है। अंतरिम सरकार के टॉप 4 मंत्रियों में सबसे ज्यादा संपत्ति की वृद्धि यूनुस की हुई है।

दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान की संपत्ति में 1 करोड़ 23 लाख रुपए की वृद्धि हुई। यूनुस के 21 में से 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार नए पीएम रहमान अंतरिम सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में इजाफे की जांच के लिए कमेटी गठित कर सकते हैं। इस सब के बीच यूनुस अब फिर से पेरिस में बसने की तैयारी में हैं। बता दें कि यूनुस बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल अवॉर्ड विजेता हैं। बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा

नाम यूनुस का शेख हसीना सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे। लेकिन यूनुस ने अपनी सरकार बनने पर केस वापस कर लिए थे।

आइटी मंत्री फैज नीदरलैंड्स लौटे

तारिक रहमान की जीत के साथ ही यूनुस सरकार में आईटी मंत्री रहे फैज अहमद तैयब नीदरलैंड्स लौट गए हैं। फैज के कार्यकाल के दौरान आइटी सेक्टर में उनके द्वारा विदेशी कंपनियों के पक्ष में दिए गए कुछ फैसलों को लेकर आपत्तियां भी आई थीं। उन पर अनावश्यक हाई-कैपेसिटी इक्विपमेंट खरीद के लिए कुछ कंपनियों को टेंडर जारी करने के भी आरोप हैं। यूनुस सरकार में पर्यावरण मंत्री सैयदा रिजवाना का कहना है कि फैज अपने परिवार के साथ नीदरलैंड्स में ही रहते हैं, वे यूनुस सरकार में शामिल होने के लिए बांग्लादेश लौटे थे।

जमात प्रमुख शफीकुर से मिले तारिक रहमान बांग्लादेश के नवनिर्वाचित पीएम रहमान ने रविवार देर शाम जमात के अमीर (प्रमुख) शफीकुर रहमान के साथ मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार रहमान ने संसद के सुचारु संचालन के लिए जमात के साथ समझौते पर सहमति भी बनाई है। बता दें कि जमात ने 32 सीटों में धांधली का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार ढाका में चीन और पाकिस्तान के दूतावासों में बैठकों के दौर तेज हो गए हैं। पाकिस्तान से लगभग 6 वरिष्ठ आर्मी अफसर पिछले एक पखवाड़े से दूतावास में डेरा जमाए हुए हैं। जमात की हार के बाद पाकिस्तान रहमान सरकार के साथ संबंधों के लिए ग्राउंड वर्क में जुटा है। पूर्व में पाक कट्टरपंथी जमात का समर्थक रहा है।

रणजी ट्रॉफी-मोहम्मद शमी का करियर बेस्ट

90 रन देकर 8 विकेट लिए, बंगाल को 26 रन की बढ़त, पडिक्कल के 232 रन से कर्नाटक मजबूत

कर्नाटक (एजेंसी)। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने एक पारी में 8 विकेट लिए। यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का बेस्ट प्रदर्शन भी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 22.1 ओवर में 90 रन देकर 8 विकेट लिए। शमी के करियर बेस्ट की वजह से बंगाल ने पहली पारी में 26 रन की

बढ़त ले ली है।वहीं, लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने 29 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 232 रन बनाए। पडिक्कल की पारी से कर्नाटक तीसरे दिन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।

इस सीजन में शानदार फॉर्म में शमी-मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में अब तक कुल 36 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट लिए थे। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट हासिल किए थे। शमी लगभग एक साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।

दूसरा सेमीफाइनल-कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में बंगाल और जम्मू-कश्मीर के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। सोमवार को मैच का तीसरा दिन चल रहा है। पहली पारी में बंगाल ने 328 रन बनाए थे। बंगाल के लिए सुदीप कुमार घरामी ने 146 रन की शतकीय पारी खेली थी। जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी डार ने 5 विकेट लिए, जबकि सुनील कुमार ने 3 विकेट झटके।इसके जवाब में जम्मू-कश्मीर की शुरुआत खराब रही। 8वें ओवर तक टीम के 13 रन पर 3 विकेट गिर गए थे।

टीम इंडिया के कोच गंभीर को आईपीएल से ऑफर

लेकिन कोच पद बना रुकावट, केकेआर को 2024 में तीसरा आईपीएल खिताब दिलाया

नईदिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स से बड़ा प्रस्ताव मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के नए निवेशकों में से एक ने गंभीर को पार्टनर, मेंटर और सीईओ का ऑफर दिया है।साथ ही उन्हें 2 से 3 प्रतिशत इक्विटी स्टेक देने की भी पेशकश की गई है। बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी के अधिकतर मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी नए मालिकों को बेच रहे हैं और सौदा ट्रांसफर प्रक्रिया में है।

गंभीर इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं

हालांकि, गंभीर फिलहाल इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम के हेड

कोच हैं, ऐसे में वे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ टीम इंडिया और किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ आधिकारिक भूमिका में नहीं रह सकता।

कॉन्ट्रैक्ट 2027 एक दिवसीय वर्ल्ड कप के बाद खत्म होगा

गंभीर के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह अभी पूरी तरह अपने मौजूदा पद पर रहेंगे। इनका बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो 2027 एक दिवसीय वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा।संन्यास के बाद गंभीर आईपीएल में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वे 2022 और 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के मेंटर रहे और टीम को दोनों बार प्लेऑफ तक पहुंचाया। इसके बाद 2024 सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ जुड़कर फ्रेंचाइजी को तीसरा आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

महिला वर्ल्ड कप जीत की हीरो को मिला बड़ा सम्मान

● साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी बनीं स्मृति मंधाना

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 के लिए 'बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर' चुना गया है। यह सम्मान उन्हें महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। सोमवार को आयोजित भव्य समारोह में देश की कई महिला खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

वीडियो संदेश के जरिए जताया आभार

इस समय स्मृति मंधाना भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां टीम मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेल रही है। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से बीबीसी का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2025 महिला क्रिकेट के लिए बेहद खास साल रहा और टीम की सफलता में योगदान देना उनके लिए गर्व की बात है।

करियर में लगातार नए कीर्तिमान

29 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट की सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार हैं। महिला वनडे इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा शतक, मौजूदा खिलाड़ियों में कुल रन के मामले में दुनिया की तीसरे नंबर की बल्लेबाज, महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी स्मृति को क्रिकेट की प्रेरणा उनके पिता और भाई से मिली, जो जिला स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

सितंबर 2025 में स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 50 गेंदों में शतक जड़ दिया था। यह 50 ओवर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय (पुरुष या महिला) द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था। इस पारी के साथ उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

अन्य खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर',पैरा एथलीट प्रीति पाल को 'पैरा स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर',पूर्व निशानेबाज अंजली भागवत को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड', विजेताओं का चयन लिएंडर पेस, दीपा मलिक और अंजू बॉबी जॉर्ज सहित प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया।

न्यूजीलैंड टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-8 में पहुंचा

कनाडा को 8 विकेट से हराया, युवराज टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बैटर बने

चेन्नई (एजेंसी)। न्यूजीलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप के 31वें मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर-8 में जगह पक्की कर ली। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम ने 15.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर टारगेट हासिल कर लिया।

फिलिप्स-रचिन के अर्धशतक

174 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र ने अर्धशतक लगाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 146 रन की साझेदारी हुई। फिलिप्स ने 36 बॉल पर नाबाद 76 रन बनाए। उन्होंने 3 कैच भी लिए। फिलिप्स को इस प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, रचिन ने 39 बॉल पर नॉटआउट 59 रन की पारी खेली। कनाडा के लिए साद बिन जफर और दिलोन हेलिगर को 1-1 विकेट मिला।

युवराज समरा का शतक

कनाडा के लिए युवराज समरा ने शतक लगाया। उन्होंने 65 बॉल पर 110 रन बनाए। 19 साल के युवराज टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के अहमद शहजाद के नाम थी, जिन्होंने 2014 में 22 साल 127 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में शतक लगाया था।टीम के लिए युवराज के अलावा कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन बनाए। युवराज और दिलप्रीत के बीच पहले विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी हुई। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी, जैकब डफी, काइल जैमीसन और जिमी नीशम को 1-1 विकेट मिला।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड- फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमन, डेरिल मिचेल (कप्तान), कोल मैककोनी, जिमी नीशम, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी।

कनाडा-दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), युवराज समरा, नवनीत धालीवाल, हर्ष ठाकेर, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), साद बिन जफर, शिवम शर्मा, दिलोन हेलिगर, जसकरन सिंह, अंश पटेल।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026

सुपर 8 में भारत के मुकाबले इन टीमों से होगा

नईदिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने लगातार तीन जीत दर्ज करते हुए सुपर 8 में शानदार अंदाज में जगह पक्की कर ली है। पाकिस्तान को 61 रन से हराकर टीम इंडिया ने ग्रुप 'ए' से अगले दौर का टिकट कटाया। अभी एक लीग मैच बाकी है, लेकिन भारत ने ग्रुप 1 में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

सुपर 8 का फॉर्मेट क्या रहेगा?

सुपर 8 में कुल 8 टीमें खेलेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में चार टीमें होंगी। आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही संभावित ग्रुप तय कर दिए थे। यानी टीम टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर रहे, उसे पहले से निर्धारित ग्रुप में ही रखा जाएगा।

ग्रुप 1 में किन टीमों से होगी भिड़ंत?

ग्रुप 1 में भारत के साथ वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया/जिम्बाब्वे में से एक टीम शामिल होगी। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका ने अपने तीनों मैच जीतकर सुपर 8 में जगह बना ली है। चौथी टीम का फैसला अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे ग्रुप 'बी' में हैं और क्वालीफिकेशन की रेस में बने हुए हैं। आयरलैंड के पास भी बाहर से मौका है। अगर कोई प्री-सीडेड टीम (जैसे ऑस्ट्रेलिया) टॉप-2 में नहीं आती, तो उसकी जगह अगली सर्वश्रेष्ठ टीम को मिलेगी।

ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्डकप से लगभग बाहर

लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर-8 में पहुंचा, निसंका ने इस टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया

कालबा (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया को टी-20 वर्ल्ड कप में एक और करारी हार झेलनी पड़ी है। उसे सोमवार के तीसरे मैच में श्रीलंका ने 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई है। अब उसकी उम्मीदें जिम्बाब्वे की हार पर टिकीं हैं। अगर जिम्बाब्वे मंगलवार को होने वाले मैच में आयरलैंड को हरा देती है, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी।

पल्लेकेले स्टेडियम में ग्रुप बी के इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 181 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका ने 182 रन का टारगेट 18 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। पथुम निसंका ने 52 बॉल पर नाबाद 100 रन की पारी खेली। इस पारी में 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। निसंका ने इस टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया। कुसल मेंडिस ने 51 रन बनाए। मार्कस स्टोयनिस को 2 विकेट मिले।

ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड ने 56 और मिचेल मार्श ने 54 रन की पारी खेली। दोनों ने शतकीय साझेदारी की। जोश इंग्लिस ने 27 और ग्लेन मैक्सवेल ने 22 रन बनाए। दुष्मंथा चमीरा को 2 विकेट मिले।

श्रीलंका ने 8 रन पर पहला विकेट गंवाया, निसंका के शतक से जीती टीम

182 रन का टारगेट चेज कर रही श्रीलंका की शुरुआत रही। टीम ने दूसरे ओवर में 8 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवाया। यहां पर कुसल परेरा एक रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मार्कस स्टोयनिस ने कैच आउट कराया।

इसके बाद पथुम निसंका (नाबाद 100 रन) ने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर टीम को 100 पार पहुंचा दिया। मेंडिस (38 गेंद पर 51 रन) के आउट होने के बाद निसंका ने पवन रत्नायके के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी। रत्नायके ने चौका लगाकर जिताया।

जिम्बाब्वे पर टिकीं ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें

श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुपर-8 में एंट्री कर ली। वहीं कंगारू टीम लगभग बाहर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का अब ओमान के खिलाफ आखिरी मैच में जीत के साथ जिम्बाब्वे के दोनों मैच हारने का इंतजार भी करनी होगी।

जिम्बाब्वे अगर श्रीलंका और आयरलैंड से हार जाए और ऑस्ट्रेलिया का रन रेट ग्रुप-बी में बेस्ट रहे, तभी कंगारू टीम क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं जिम्बाब्वे ने आखिरी दोनों में से एक भी मैच जीत लिया तो टीम श्रीलंका के साथ सुपर-8 में जगह बना लेगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोस इंग्लिस, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोयनिस, टिम डेविड, कूपर कोनोली, जैवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, और एडम जम्पा।

श्रीलंका- दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, दुनिथ वेल्लालागे, दुषन हेमंथ, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा, मथीश पथिराना।

5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी

इमरान खान के इलाज की मांग, इनमें भारत के दो, पाकिस्तान का कोई नहीं

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपील की है कि 73 साल के इमरान को जेल में उचित इलाज दिया जाए।

इस चिट्ठी पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रियरली, डेविड गावर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट ने साइन किए हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, इस चिट्ठी पर किसी भी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते वसीम अकरम, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी समेत कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर इमरान के लिए उचित इलाज की मांग की थी।इमरान खान (बाएं) ने पाकिस्तान के लिए 1971 से 1992 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था।

इमरान की एक आंख की 85 प्रतिशत रोशनी खत्म-इमरान खान की एक आंख की करीब 85 प्रतिशत रोशनी चली गई है। यह खुलासा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की

तरफ से नियुक्त वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान जेल प्रशासन से कई महीनों आंखों में धुंधलापन होने की शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंख की रोशनी अचानक चली गई। जांच के दौरान पिम्स अस्पताल के एक आई एक्सपर्ट को बुलाया गया था। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ।इलाज और इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी दाईं आंख में अब सिर्फ लगभग 15 प्रतिशत रोशनी बची है। वहीं इमरान का कहना है उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत नहीं दी गई है।

रिपोर्ट- इमरान खान मानसिक दबाव से जूझ रहे-रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से इमरान खान को अडियाला जेल में लगातार अलग-थलग रखा गया है। उनके वकील ने मुलाकात के बाद बताया कि वो काफी परेशान और मानसिक रूप से दबाव में नजर आए। 73 साल के इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें अपने निजी डॉक्टरों से इलाज कराने की इजाजत नहीं दी गई। उनका रेगुलर ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ। यहां तक कि दो साल में उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया, जबकि उन्होंने कई बार इसकी मांग की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनके परिवार और वकीलों से मिलने पर भी पाबंदियां लगाई गईं। अदालत के आदेश के बावजूद उनकी बहनों को नियमित रूप से मिलने नहीं दिया गया। हालांकि हाल ही में जेल प्रशासन बदलने के बाद अब उन्हें अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार 30 मिनट मिलने की इजाजत मिली है।उनके बेटों कासिम और सुलेमान से 2025 में सिर्फ दो बार फोन पर बात करने दी गई। पिछले पांच महीनों से उन्हें अपने मुख्य वकील और कानूनी टीम से भी मिलने नहीं दिया गया।रिपोर्ट के अंत में चेतावनी दी गई है कि अगर तुरंत बेहतर मेडिकल जांच, साथ ही परिवार और वकीलों से मिलने की सुविधा बहाल नहीं की गई, तो उनकी सेहत को और गंभीर खतरा हो सकता है।

मनरेगा श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 20 फरवरी को सभी पंचायत भवनों में विशेष शिविर सुबह 7 बजे से

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला बेमेतरा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 फरवरी 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायत भवनों में प्रातः 7 बजे से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसे विशेष अभियान के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है, ताकि शत-प्रतिशत श्रमिकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जा सके। मनरेगा कार्यों में वास्तविक श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा डिजिटल माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी आवश्यक किया गया है। ई-केवाईसी पूर्ण होने पर श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और उन्हें समय पर भुगतान प्राप्त होगा।

ई-केवाईसी के प्रमुख लाभ

पारदर्शिता में वृद्धिः श्रमिकों की उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।भ्रष्टाचार में कमीः डिजिटल सत्यापन के माध्यम से फर्जी प्रविष्टियों पर रोक लगेगी। बेहतर निगरानीः श्रमिकों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव होगी। समय पर भुगतानः सत्यापित श्रमिकों को रोजगार एवं मजदूरी का लाभ शीघ्र और सुगमता से मिलेगा।

ई-केवाईसी नहीं कराने पर संभावित समस्याएं

भविष्य में मनरेगा अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। जॉब कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। मनरेगा के तहत मिलने वाले सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया जारी है, किंतु 20 फरवरी को विशेष अभियान चलाकर शेष श्रमिकों का सत्यापन पूर्ण किया जाएगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की गई है कि वे अपने आधार कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि को अपने ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। ऐसे श्रमिक जो वर्तमान में गांव से बाहर रह रहे हैं अथवा अन्यत्र कार्यरत हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे समय निकालकर इस अभियान में सहभागी बनें, ताकि भविष्य में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार एवं अन्य लाभों से वंचित न होना पड़े। ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए श्रमिक अपने ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव अथवा रोजगार सहायक से तत्काल संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने इसे श्रमिक हित में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए सभी पात्र हितग्राहियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है, ताकि मनरेगा योजना का लाभ पारदर्शी एवं सुचारू रूप से सभी तक पहुंच सके।

गंगालूर इलाके में नक्सलियों की साजिश नाकाम, विस्फोटक भी बरामद

सीआरपीएफऔर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी तैयारी

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार । जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इरामांगी गांव के पास जंगल में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सीआरपीएफ की 85वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस ने छुपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुख्ता सूचना मिलने पर 15 फरवरी की सुबह कावड़गांव कैंप से करीब 3.8 किलोमीटर दूर घने जंगल में संयुक्त एरिया डॉमिनेशन अभियान शुरू किया गया। अभियान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहायक कमांडेंट हेमंत भट्ट के नेतृत्व में चलाया गया। तलाशी के दौरान डॉग स्क्वायड के फिडल ने एक संदिग्ध स्थान की ओर इशारा किया। इसके बाद बीडीडीएस टीम ने मौके को सुरक्षित करते हुए जांच की। सुबह करीब 10 बजे वहां से दो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, लगभग डेढ़ किलो गन पाउडर, चार जिलेटिन रॉड और 25 से 30 मीटर कोर्डेक्स वायर बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन जवानों की सतर्कता से उनकी योजना विफल हो गई। लगातार चलाए जा रहे अभियानों से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर दबाव बना हुआ है। कार्रवाई के बाद कमांडेंट सुनील कुमार राही ने अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

समाज सेविका सरिता डहरिया ने अपना जन्मदिन विकलांग बच्चों व वृद्ध लोगो के साथ मनाया

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

समाज सेविका सरिता डहरिया ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रांजल वेलफेयर फाउंडेशन के छोटे बच्चे व विकलांग बच्चों को टी शर्ट तथा फ्रूट वितरित किये साथ मे नन्हे बच्चों के साथ केक काटे साथ मे सियान सदन के असहाय बुजुर्गो को साड़ी और फ्रूट वितरित किए। साथ मे बुजुर्ग महिलाओ के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया यह एक सराहनीय पहल है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनमोल पल को असहाय बुजुर्गों के बीच आशीर्वाद लेते हुए मनाया। सरिता डहरिया की इस पहल से न केवल असहाय बुजुर्गों बल्कि उनके इस कार्य से यह भी दर्शाया कि वे समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उनकी यह पहल समाज में एक अच्छा संदेश देती है और लोगों को प्रेरित करती है। सरिता डहरिया का मानना है कि सहयोग करने से समाज आगे बड़ता है तथा थोड़ा सा सहयोग से लोगो को मदद मिलती है आगे उन्होने कहा कि योग्य इंसान को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंद लोगों का सहयोग करें। उनका यह मानना है कि हमें समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। समाज सेविका सरिता डहरिया की इस पहल से पता चलता है कि वे समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं और वे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उनकी यह पहल समाज में एक अच्छा संदेश देती है और लोगों को प्रेरित करती है। सरिता डहरिया पुर्व राज्य मंत्री हरिदास भारद्वाज कि बेटी व जिला शिक्षा अधिकारी जे.आर. पत्नी है उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी बेटी जानवी डहरिया , भाई जितेंद्र भारद्वाज उपस्थिथि रहे

नूकनपाल में सीआरपीएफका सिविक एक्शन आयोजित, ग्रामीणों को मिली जरूरत की सामग्री

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा के साथ लोगों का भरोसा जीतने के लिए बी/62 वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नूकानपाल में सिविक एक्शन कार्यक्रम किया। इसमें आसपास के कई गांवों से पहुंचे जरूरतमंद ग्रामीणों और बच्चों को रोजमर्रा के काम आने वाली सामग्री दी गई।कार्यक्रम पुलिस उप महानिरीक्षक बी.एस. नेगी और कमांडेंट दीपक मेहरा के मार्गदर्शन में हुआ। सहायक कमांडेंट अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में नूकानपाल, धाराभम, बोदल-पुंगर, भुसगुड़ी और होसुरपाल के ग्रामीण शामिल हुए।इस दौरान कंबल, सोलर लैंप, खेल सामग्री, पढ़ाई का सामान और कृषि से जुड़ी वस्तुएं बांटी गई। अधिकारियों ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और इलाके में शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से गांवों के साथ जुड़ाव बढ़ता है और विकास की राह आसान होती है। ग्रामीणों ने भी पहल की तारीफकरते हुए सीआरपीएफ का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में निरीक्षक आकाश साहू, थाना प्रभारी मोदकपाल, बटालियन के अधिकारी-जवान, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

मनरेगा में ई-केवाईसी प्रगति धीमी: 10 रोजगार सहायकों और 29 तकनीकी सहायकों को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ई-केवाईसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले की सभी जनपद पंचायतों में कार्यरत 10 रोजगार सहायकों एवं 29 तकनीकी सहायकों को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि ई-केवाईसी कार्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है, इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं की गई। कई बार निर्देश एवं समीक्षा के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। रोजगार सहायकों को ग्राम स्तर पर श्रमिकों के ई-केवाईसी पंजीयन में लापरवाही बरतने तथा निर्धारित प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। वहीं तकनीकी सहायकों को कार्यों की प्रविष्टि, सत्यापन एवं पोर्टल पर अद्यतन प्रगति सुनिश्चित नहीं करने के संबंध में कारण बताने नोटिस जारी किया गया है।सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

आभा कार्ड से रखा जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के बीमारी और इलाज का रिकार्ड

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि, आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है, जो देशवासियों को डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करता है। यह 15 अंकों का अद्वितीय नंबर है, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है तथा विभिन्न अस्पतालों व डॉक्टरों के बीच साझा करने योग्य बनाता है। कार्ड बनाने हेतु आधार या मोबाइल नंबर से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। यह डिजिटल सुरक्षित, निःशुल्क, गोपनीय और पेपरलेस है। आभा कार्ड से एकीकृत स्वास्थ्य डेटा, टेस्ट रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, वैक्सीनेशन, इतिहास, एक जगह संग्रहित से तत्काल लाभ होगा। कहीं भी डॉक्टर को क्यूआर कोड स्कैन कर पूरा मेडिकल हिस्ट्री मिल जाता है।बैठक में जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, सदस्य सुशीला साहू, अभिलाषा नायक एवं अन्य सदस्यों का आभा कार्ड पंजीकृत कर वितरित किया गया। बैठक में आभा कार्ड के व्यापक प्रचार- प्रसार हेतु विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को आभा कार्ड से जोड़ा जाएगा।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एफ आर निराला, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी रामलाल सिदार, अवधेश पाणिग्राही, डीपीएम एन एल इजारदार, डीपीसी रोशन सचदेव, प्रभारी बीपीएम एवं विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

पेद्दाजोजेर के जंगल में 7 फीट ऊंचा माओवादी स्मारक ध्वस्त, भोपालपटनम के कोण्डापड़गु में दो आईईडी बरामद,मौके पर किया निष्क्रिय

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। जिले में चल रहे एन्टी नक्सल ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों ने गंगालूर थाना क्षेत्र के पेद्दाजोजेर जंगल में माओवादियों द्वारा बनाया गया करीब 7 फीट ऊंचा स्मारक गिरा दिया। यह कार्रवाई डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा 202 की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन के दौरान की। सर्चिंग के समय जवानों को जंगल के भीतर यह स्मारक दिखाई दिया। सुरक्षा के लिहाज से इसे तुरंत ध्वस्त कर दिया गया, ताकि माओवादियों के प्रतीकात्मक ढांचे खत्म किए जा सकें। उधर, भोपालपटनम थाना क्षेत्र के कोण्डापड़गु जंगल में केरिपु 214 की टीम डिमाइनिंग पर निकली थी। इसी दौरान बीयर बोतलों में छिपाकर लगाए गए दो आईईडी बरामद हुए। बीडीडी टीम ने सतर्कता बरतते हुए दोनों विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। माओवादियों के प्रभाव और डर का माहौल बनाने वाले स्मारकों और अन्य ढांचों को चिन्हित कर हटाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में सामान्य हालात मजबूत हो सकें।

फसल मजबूत करने अब मिलेगा नया खाद, अधिसूचना जारी

सल्फर कोटेड यूरिया को नाम दिया गया यूरिया गोल्ड

यूरिया गोल्ड के 40 किलो की बोरी में होगा 37 प्रतिशत नाइट्रोजन और 17 प्रतिशत सल्फर

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विगत 23 जनवरी को ÷ सल्फर कोटेड यूरिया÷ खाद की अधिसूचना जारी की गई है। यह किसानों के लिए अच्छी खबर है। नई खाद 40 किलो की बोरी में उपलब्ध होगी। इसमें 37 प्रतिशत नाइट्रोजन और 17 प्रतिशत सल्फर होगा। सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण यह खाद पीले रंग की होगी, इसलिए इसका नाम ÷यूरिया गोल्ड÷ भी रखा गया है। फसलों को अच्छी पैदावार और ज्यादा उत्पादन के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है।नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और तनों की बढ़वार में मदद करता है। सल्फर फसल में दाना भरने, तेल और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, दालें, मिर्च, लहसुन और प्याज जैसी फसलों के लिए सल्फर बहुत जरूरी माना जाता है। कई सालों से किसान मुख्य रूप से यूरिया और एनपीके खाद का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में सल्फर की कमी हो गई है। सल्फर की कमी से फसल कमजोर होती है और उत्पादन कम हो सकता है। यूरिया गोल्ड के उपयोग से नाइट्रोजन के साथ-साथ सल्फर भी मिलेगा, जिससे फसल मजबूत और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वे अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराकर संतुलित और सही मात्रा में खाद का उपयोग करें। पराली न जलाएं, हरी खाद अपनाएं और फसल चक्र में दलहन-तिलहन फसलों को शामिल करें। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित खाद के उपयोग से मिट्टी की सेहत सुधरेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।